जीवन दर्शन

तुम अपने मिनटों का ध्यान रखो, घंटे अपनी परवाह खुद कर लेंगे
- अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड

दैनिक ग्लोबल हेराल्ड

LOCAL TO GLOBAL

महानगर संस्करण

www.globalherald.news

शुक्रवार 24 अप्रैल, 2026 ■ वर्ष 15 ■ अंक 73 ■ इंदौर-भोपाल से प्रकाशित ■ पेज 8 ■ मूल्य रु 2.00

सैमसन का शतक, सीएसके ने दर्ज की आईपीएल इतिहास की...

पृष्ठ 8 पर

होर्मुज में माइन बिछा रहे जहाजों को तबाह करें: ट्रम्प

होर्मुज हमारे नियंत्रण में, परमिशन के बिना कोई भी जहाज यहां से निकल नहीं सकता

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी ■

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैंने अमेरिकी नेवी को आदेश दिया कि होर्मुज में बारूदी सुरंगें (माइन) बिछा रहे छोटे से छोटे जहाजों को बिना हिचकिचाहट तबाह कर दिया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि बारूदी सुरंग हटाने वाले उनके जहाज स्ट्रेट को साफ कर रहे हैं। उन्होंने इस काम को तीन गुना तेजी से करने का आदेश दिया है। दूसरे पोस्ट में उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह अमेरिका के नियंत्रण में है। अमेरिकी नेवी की परमिशन के बिना कोई भी जहाज यहां से निकल नहीं सकता है। जब तक ईरान किसी समझौते पर नहीं आता, तब तक स्ट्रेट पूरी तरह बंद रहेगा।

उन्होंने दावा किया कि ईरान को यह समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि उनका नेता कौन है। ईरान युद्ध में बुरी तरह हार रहा है। अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद पर लगी पाबंदियों में दी गई छूट को 30 दिन के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला करीब 10 देशों की मांग पर लिया गया है, जो तेल की कमी का सामना कर सकते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ चल रहे युद्धविराम (सीजफायर) को आगे बढ़ाया गया। ट्रम्प ने कहा कि ईरान में इस समय नेतृत्व और सरकार में एकजुटता नहीं है। ईरान ने किसी भी तरह के सीजफायर से इनकार किया है। मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा कि सीजफायर तभी संभव है जब नाकाबंदी हटाई जाए। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड (आईआरजीसी) ने होर्मुज स्ट्रेट में दो जहाजों को जब्त कर लिया और कहा कि इस रास्ते की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। इससे पहले इन पर गोलीबारी भी की गई।

होर्मुज संकट से 3 करोड़ लोग गरीब होंगे

संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि अगर ईरान से जुड़ा युद्ध कल भी खत्म हो जाए, तब भी दुनिया भर में 3 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी में धकेल दिए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अलेक्जेंडर डी क्रू ने कहा कि वैश्विक जीडीपी का 0.5% से 0.8% तक नुकसान हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर कमजोर देशों पर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ऊर्जा कीमतों में उछाल और खाद्य असुरक्षा इस संकट की बड़ी वजह हैं। होर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि बड़ी मात्रा में उर्वरक (फर्टिलाइजर) भी गुजरता है। इसके बाधित होने से असर और गहरा हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले महीनों में खाद्य संकट और गंभीर हो सकता है। अभी बुवाई का समय है।

युद्ध लंबा खिंचने की आशंका से तेल महंगा

मिडिल ईस्ट में युद्ध लंबा चलने की आशंका के बीच तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रेंट क्रूड करीब 1.9% बढ़कर लगभग 104 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। यह लगातार चौथे दिन बढ़ा। वहीं डब्ल्यूटीआई भी बढ़कर करीब 94.6 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता न होने से निवेशक अब लंबे संघर्ष और होर्मुज स्ट्रेट के लंबे समय तक बंद रहने की आशंका मान रहे हैं। इसका असर शेयर बाजारों पर भी पड़ा है। अमेरिका में एस एंड पी 500 और नैस्डैक के फ्यूचर्स कमजोर शुरूआत का संकेत दे रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में वोटिंग का नया रिकॉर्ड पहले फेज में 93% मतदान हुआ

ममता बोलीं- एसआईआर के विरोध में बंपर वोटिंग

कोलकाता/चेन्नई ■

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में गुरुवार को बंपर वोटिंग हुई। बंगाल की 294 सीटों में से 152 सीटों पर पहले फेज में 92.72% मतदान हुआ। वहीं, तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 85.14% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के आंकड़े रात 9 बजे तक हैं। इनमें बदलाव हो सकता है।

दोनों राज्यों में आजादी के बाद अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। इससे पहले तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मतदान 2011 में 78.29% था, जबकि बंगाल में 2011 में 84.72% मतदान दर्ज किया गया था। ममता ने वोटिंग के बाद कहा- बंगाल की जनता ने एसआईआर के खिलाफ बंपर वोटिंग की है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि टीएमसी का सूरज ढल चुका है। इससे पहले असम, केरलम और पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल को रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी। असम के इतिहास में सबसे ज्यादा 85.91%, पुडुचेरी में 90% और केरलम में 1987 के बाद सबसे ज्यादा 78.27% वोटिंग हुई थी। पाचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को एकसाथ आएंगे।

बंगाल में वोटिंग के दौरान मारपीट-झड़प

- बंगाल के दक्षिण मिदनापुर में कुमारगंज सीट से भाजपा कैंडिडेट सुवेंदु सरकार को भीड़ ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा।
- पश्चिम बर्धमान जिले के बर्नपुर में आसनसोल साउथ सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर हमला हुआ।
- बीरभूम के बोधपुर गांव में ईवीएम खराब होने के बाद लोगों ने पुलिस और सेंट्रल फोर्स पर पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। घटना में कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए।

न्यूज ब्रीफ

मुझसे गलती हो गई, कोर्ट में बोला आईआरएस अफसर की बेटी का हत्यारा, रेप

नई दिल्ली। नई दिल्ली के पॉश इलाके कैलाश हिल्स में एक आईआरएस अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की नृशंस हत्या और रेप के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने इस मामले में 19 वर्षीय पूर्व घरेलू सहायक राहुल मीणा को गिरफ्तार किया है, जिसने महज 12 घंटों के भीतर दो राज्यों में दो खौफनाक वारदातों को अंजाम दिया। राहुल मीणा के आतंक की शुरूआत राजस्थान के अलवर से हुई। दरिंदे राहुल ने मंगलवार रात अलवर में अपने ही एक दोस्त की पत्नी के साथ रेप किया। वह दोस्त के साथ एक शादी में गया था, लेकिन वहां से चुपचाप लौटकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया और महिला को जान से मारने की धमकी दी। वहां से फरार होकर आरोपी बुधवार सुबह दिल्ली पहुंचा। बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे वह कैलाश हिल्स स्थित अपने पूर्व मालिक (IRS अधिकारी) के घर पहुंचा। उसे घर के रास्तों और परिवार की दिनचर्या का पूरा पता था।

हवाई किराया मामले में डीजीसीए सख्तः इंडिगो को चेतावनी पत्र जारी

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एक बार फिर रडार पर है। विमानन नियामक महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो को चेतावनी पत्र जारी किया है। यह मामला दिसंबर 2025 के दौरान सरकार की ओर से घरेलू हवाई किराए पर लगाए गए फेयर कैप यानी हवाई किराए की सीमा के उल्लंघन से जुड़ा है। इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने गुरुवार को इस नियामक कार्रवाई की औपचारिक जानकारी दी है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, डीजीसीए ने यह कदम उन हवाई किरायों की जांच के बाद उठाया है, जो एयरलाइन ने दिसंबर 2025 में यात्रियों से वसूले थे। उस समय सरकार ने हवाई किरायों के लिए एक निश्चित सीमा तय की थी, जिससे यात्रियों से मनमाना किराया न वसूला जा सके। नियामक ने पाया कि इंडिगो ने कुछ मार्गों पर इन नियमों का पालन नहीं किया था। डीजीसीए ने एयरलाइन को भविष्य के लिए सख्त हिदायत दी है। नियामक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एयरलाइन को सरकारी आदेशों का पालन करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में नियमों का किसी भी स्तर पर उल्लंघन न हो।

मालेगांव ब्लास्ट में मरे थे 31 लोग अपराधी कोई नहीं?

मुंबई। मालेगांव ब्लास्ट मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए चारों आरोपियों को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के चार्ज फ्रेम करने के आदेश को रद्द कर दिया। अब इस मामले में कोई भी ट्रायल नहीं चलेगा। जनवरी 2026 में ही ट्रायल पर रोक लगाई जा चुकी थी। इस तरह 19 साल बाद यह मामला पूरी तरह से खत्म हो गया है। इस धमाके में 31 लोग मारे गए थे और 312 घायल हुए थे। यह धमाका 8 सितंबर 2006 को दोपहर 1.50 बजे मालेगांव में चार बम ब्लास्ट हुए थे। इनमें हमीदिया मस्जिद, बड़ा कब्रिस्तान के परिसर में और एक मुशावर्त चौक पर ब्लास्ट पर हुआ था।

केन्द्र सरकार ने मानी सीएम मोहन यादव की मांग, किसानों को मिली बड़ी राहत

अब प्रदेश में समर्थन मूल्य पर इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी होगी

भोपाल ■

मध्यप्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मांग को केन्द्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब प्रदेश में समर्थन मूल्य पर इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जाएगी। पहले मध्यप्रदेश में 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी का टारगेट रखा गया था, लेकिन प्रदेश में हुई गेहूं की बंपर पैदावार को देखते हुए सीएम मोहन यादव ने टारगेट बढ़ाने का आग्रह केन्द्र सरकार से किया था जिसे केन्द्र सरकार ने सहमति देते हुए सीएम मोहन यादव की मांग पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की सीमा बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दी है।

सीएम मोहन ने जताया आभार

गेहूं खरीदी की सीमा 100 लाख टन किए जाने के बाद सीएम यादव ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का आभार जताया है। सीएम ने अपनी पोस्ट में लिखा है- मप्र के किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय...प्रदेश में इस वर्ष गेहूं उत्पादन बढ़ा है, इसलिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया था।

एमपी में 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी होगी

केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भेजकर एमपी में गेहूं खरीदी का कोटा बढ़ाए जाने की जानकारी दी है। शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री प्रल्हाद जोशी से मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी के टारगेट को को लेकर चर्चा की थी, इस बात का जिक्र भी मंत्री प्रल्हाद जोशी ने अपने पत्र में किया है। पत्र में प्रल्हाद जोशी ने जानकारी दी है कि मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी की समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की सीमा 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दी गई है।

पीएम मोदी का हावड़ा में रोड-शो बोले-भाजपा का भरोसा जीतेगा

टीएमसी का भाजपा को जवाब- न आए हो न आओगे, भवानीपुर में ममता की पदयात्रा

कोलकाता ■

पश्चिम बंगाल में गुरुवार को 152 सीटों पर वोटिंग हुई तो 142 सीटों पर चुनाव प्रचार चलता रहा। पीएम मोदी ने कृष्णानगर और मथुरापुर में जनसभा की और हावड़ा में रोड शो किया। मोदी ने कहा कि जनता ने तय कर दिया है कि 4 मई को परिणाम नहीं, परिवर्तन आएगा।

टीएमसी हारेगी और भाजपा का भरोसा जीतेगा। अब का मतदान सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मैं यहां परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। प्रधानमंत्री की रैली के बाद टीएमसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा- न आए हो, न आओगे। जिस वक्त मोदी हावड़ा में रोड शो कर रहे थे, उसी वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर में रोड शो किया। ममता यहीं से विधायक हैं। भवानीपुर में 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। यहां से सुवेंदु अधिकारी भाजपा प्रत्याशी हैं।

मातम के बीच 'मातम': अंत्येष्टि में गए थे, लौटते समय आठ रिश्तेदारों को खाई में खींच ले गई मौत

टिहरी ■

टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में नैलचामी क्षेत्र के चकरेड़ा गांव से 10 लोग हरिद्वार अंत्येष्टि में गए थे। लौटते समय दोपहर करीब 2.15 बजे वाहन चंबा-कोटीकॉलोनी मोटर मार्ग पर नैल गांव के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का पता चलते ही चंबा थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने खाई में उतर कर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

दो घायलों को खाई से निकालकर जिला अस्पताल बौराड़ी पहुंचाया गया जबकि वाहन सवार आठ अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वाहन दुर्घटना की सूचना मिलने पर डीएम नितिका खंडेलवाल, विधायक किशोर उपाध्याय, एसएसपी श्वेता चौबे और सीएमओ डॉ. श्याम विजय ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल बौराड़ी पहुंचवाया।

'व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़कर, सभी विचारों का सम्मान', सबरीमाला मामले में 'सुप्रीम' टिप्पणी

नई दिल्ली ■

सबरीमाला मंदिर से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि वह सभी विचारों और जानकार लोगों की राय का सम्मान करता है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आने वाली जानकारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट की यह टिप्पणी उस समय आई, जब धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों पर बड़ी बहस चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इसमें महिलाओं के धार्मिक स्थलों में प्रवेश और विभिन्न धर्मों में प्रचलित परंपराओं के दायरे पर विचार हो रहा है।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने विभिन्न स्रोतों से ज्ञान लेने की बात कही। इसी पर जस्टिस बी वी नागरत्ना ने हल्के अंदाज में कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने साफ कहा कि कोर्ट सभी विद्वानों और विचारकों का सम्मान करता है, लेकिन व्यक्तिगत राय को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि अदालत तथ्यों और कानून के आधार पर ही फैसला करेगी। कोर्ट ने संकेत दिया कि गलत या अपुष्ट जानकारी को आधार नहीं बनाया जा सकता।

सबरीमाला मामला क्या है?

सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर पहले रोक थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने इस प्रतिबंध को असंवैधानिक बताते हुए हटा दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह परंपरा महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है। अब इस फैसले से जुड़े व्यापक मुद्दों पर फिर से सुनवाई हो रही है।

महिलाओं के मस्जिद में नमाज के लिए जाने पर कोई रोक नहीं

नई दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (मुस्लिम बोर्ड) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि महिलाओं के मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने पर कोई रोक नहीं। सीनियर एडवोकेट एम.आर. शमशाद ने मुस्लिम बोर्ड की ओर से 9 जजों की बेंच के सामने यह बात रखी। यह बेंच सबरीमाला मामले की सुनवाई कर रही है। मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की मांग करने वाली रिट याचिकाएं भी सबरीमाला मामले के साथ जोड़ दी गईं, क्योंकि वहां भी अनुच्छेद 25 और 26 के दायरे से जुड़े संवैधानिक सवाल उठते हैं।

व्यंग्य : ममता ने लोकतंत्र खतरे में डाला :जनता का क्या फैसला..?

ग्लोबल हेराल्ड न्यूज एनालिसिस GHNA

दिलीप शर्मा (वरिष्ठ पत्रकार)

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आईपैक मामले में हस्तक्षेप करने पर कड़ी फटकार लगाते हुए उनके इस कृत्य को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया. वैसे भी बंगाल में चुनाव पूर्व हिंसात्मक गतिविधियों के कारण ममता राज, जंगलराज जैसा चर्चित रहा है. ऐसे में इस बार जनता का क्या फैसला आता है. जंगलराज क्या जनता फिर पसंद करेगी, बंगाल व तमिलनाडु दोनों राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई, परिणाम 4 मई को आएंगे ..?

बंगाल, तमिलनाडु में बम्पर वोटिंग : क्या कांग्रेस का कहा सच..?

पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को हुए पहले चरण में बम्पर वोटिंग हो चुकी है, क्या यह ममता के जंगलराज में बदलाव का संकेत है.. जवाब दूसरे चरण की वोटिंग बाद 4 मई को परिणाम आने पर मिलेगा. वैसे पहले चरण का गणित ही इस मुकाबले को सबसे अहम बनाता है. विधानसभा चुनाव 2021 में बीजेपी ने पहले चरण की 152 में से 59 सीटें जीती थीं, जबकि दूसरे चरण की 142 सीटों में वह केवल 18 पर सिमट गई थी. सत्ता की राह में बीजेपी के लिए पहले चरण में बढ़त बनाना बेहद जरूरी है. यहां कमजोर पड़ी, तो आगे की राह कठिन हो सकती

है.दरअसल, बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास भी इस चिंता को बढ़ाता है. 2019 लोकसभा चुनाव में 15 लोगों की मौत और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. 2021 विधानसभा चुनाव में हिंसा के 1300 मामले सामने आए और 17 लोगों की जान गई. 2023 पंचायत चुनाव में 45 मौतें हुईं, जिनमें से 18 सिर्फ मतदान के दिन बताई गईं. 2024 लोकसभा चुनाव में भी 10 मौतों और 100 से ज्यादा घटनाओं का दावा किया गया. इसी पृष्ठभूमि में निर्वाचन आयोग ने इस बार सख्ती बढ़ा दी फिर भी हिंसा हुई और बम भी फेंके गए.उल्लेखनीय है कि 23 अप्रैल को तमिलनाडु में भी 234 सीटों के लिए भी बम्पर वोटिंग हुई. दोनों राज्यों के बारे में हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की भले जबान फिसली और खबर सुर्खियों में रही कि दोनों राज्यों में बीजेपी जीतेगी तो क्या यह जबान फिसलना या फिर कांग्रेस के हालात की हकीकत. खैर जो भी हो वैसे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कृत्य से सुप्रीम कोर्ट भी खफा रहा है और चुनाव आयुक्त के विरुद्ध भी हार चुकी ममता सरकार क्या अब जाने की तैयारी में है.. पता चलेगा..? वैसे भी बंगाल में ममता के लिए राह आसान नहीं है और हो सकता है कि तमिलनाडु में भी बीजेपी मजबूती से उभरे, हालांकि जनता के मन में क्या रहा है 4 मई को ही पता चलेगा..?

जज से बहस वाले वीडियो पर केजरीवाल को नोटिस

नई दिल्ली ■

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। याचिका बिना इजाजत कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड करने और उसे सोशल मीडिया पर सकुर्लेट करने को लेकर है। कोर्ट ने सभी वीडियो डिलीट करने और लिंक हटाने के निर्देश दिए हैं।

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका एडवोकेट वैभव सिंह ने लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया, पत्रकार रवीश कुमार और अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सूचना मंत्रालय को भी पक्षकार बनाया है। हाईकोर्ट को बताया गया कि जिन लिंक पर आपत्ति थी, उन्हें गूगल और मेटा ने पहले ही हटा दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। एक दिन पहले यह मामला चीफ जस्टिस की बेंच में लिस्ट था। लेकिन, जस्टिस तेजस करिया ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद इसे जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत अरोड़ा की बेंच में रखा गया। वैभव सिंह का आरोप था कि 13 अप्रैल की सुनवाई को बिना परमिशन रिकॉर्ड किया गया और सोशल मीडिया पर सकुर्लेट किया गया। यह सुनवाई केजरीवाल की उस अर्जी पर हुई थी, जिसमें उन्होंने जज स्वर्णकांता से खुद को केस से अलग करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के

इंदौर के एम.टेक स्टूडेंट को एक्स ने दिया 72 लाख का पैकेज, प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

इंदौर शहर में डीएवीवी ने अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 विवि के लिए प्लेसमेंट के लिहाज से मजबूत रहा। खास बात रही कि एक ओर हाई पैकेज के ऑफर मिले तो औसत पैकेज और कंपनियों की संख्या में भी पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई। विवि द्वारा जारी प्लेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार, इस साल कुल 271 कंपनियों ने कैंपस ड्राइव में हिस्सा लिया और 1091 ऑफर दिए।

पिछले वर्ष यह आंकड़ा 219 कंपनियां और 1039 ऑफर का था। यानी कंपनियों की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा हुआ, जिसका सीधा फायदा छात्रों को मिला। प्लेसमेंट में शामिल विद्यार्थियों में 56 प्रतिशत छात्र और 44 प्रतिशत छात्राएं रहीं। सबसे बड़ा पैकेज इस सत्र का सबसे ज्यादा 72 लाख का सालाना पैकेज आइआइपीएस के एमटेक छात्र आदित्य बंसल को एक्स कॉम ने दिया।

अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में मिला प्लेसमेंट

इसके अलावा आइईटी के विद्यार्थियों को भी बड़े प्लेसमेंट पर मौके मिले। श्रुति शर्मा, कृति श्रीवास्तव और अनुज मालवीय को अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और वालमार्ट में प्लेसमेंट मिला। इस बार औसत पैकेज बढ़कर 5.31 लाख रुपए सालाना हो गया, जबकि पिछले साल यह 5.14 लाख था। यह संकेत है कि न सिर्फ अवसर बढ़े हैं, बल्कि उनकी गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। कुलगुरु प्रो. राकेश सिंघई के मुताबिक, प्लेसमेंट को और बेहतर बनाने के लिए विवि लगातार काम कर रहा है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडस्ट्री एंगेजमेंट, एलुमिनाई नेटवर्क को मजबूत करना, हाई पैकेज कंपनियों को आकर्षित करना और सॉफ्ट स्किल्स व लैंग्वेज ट्रेनिंग जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही यह कोशिश भी है कि चुनिंदा विभागों तक सीमित अच्छे प्लेसमेंट को अन्य विभागों तक भी बढ़ाया जाए।

गैस लाइन की खुदाई से लगा जाम, स्कूल बसों समेत सैकड़ों वाहन फंसे, अधिकारियों के छूटे पसीने

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

इंदौर के चाणक्यपुरी चौराहे पर आज दोपहर में लगे ट्रैफिक जाम ने अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए। यहां नर्मदा और अवंतिका गैस लाइन डालने के उद्देश्य से की गई सड़क खुदाई पिछले 15 दिनों से आम जनता के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। गुरुवार सुबह स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वाहन चालकों को एक से डेढ़ से दो घंटे तक रेंगना पड़ा। इस भारी जाम के कारण स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और कई बसें समय पर स्कूल नहीं पहुंच सकीं। ई-रिक्शा और दोपहिया वाहनों की भारी भीड़ के बीच लोग घंटों फंसे रहे।

पुलिस अधिकारियों ने मौके पर संभाला मोर्चा

जाम की गंभीरता को देखते हुए जोन-4 के डीसीपी आनंद कल्यादगी, एसीपी शिवेंद्र जोशी और अन्य ट्रैफिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू रूप से शुरू करवाया जा सका। पुलिस ने इस दौरान मौके पर मौजूद ठेकेदार से खुदाई और उससे संबंधित अनुमति के दस्तावेजों की मांग की।

बिना अनुमति खुदाई पर होगी एफआईआर

अन्नपूर्णा पुलिस ठेकेदार को पूछताछ के लिए थाने ले गई। एडिशनल डीसीपी संतोष कौल के मुताबिक अवंतिका गैस एजेंसी ने पाइप लाइन विस्तार के लिए पूरे चौराहे को खोदकर छोड़ दिया। पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि क्या इस कार्य के लिए वैध अनुमति ली गई थी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि अनुमति नहीं पाई गई, तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

अव्यवस्थित खुदाई से शहरवासी परेशान

राजेंद्र नगर ब्रिज से तालाब क्षेत्र और केसरबाग ब्रिज से गोपुर चौराहे तक वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। अन्नपूर्णा रोड पर क्रोमा शोरूम से हनुमान मंदिर तक सड़क की स्थिति जर्जर है और गणेश मंदिर के पास बीच सड़क पर बड़ा गड्ढा हादसे को न्योता दे रहा है। खुदाई के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन या किसी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं होने से स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है।

चेतावनी के बाद भी एजेंसी की लापरवाही

ट्रैफिक एसीपी जगदीश पाटिल ने करीब 15 दिन पहले ही अवंतिका गैस कंपनी को इस संभावित जाम और समस्या के प्रति सचेत किया था। इसके बावजूद कंपनी प्रबंधन ने सुरक्षा या यातायात प्रबंधन के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए। सुबह और शाम के समय जब वाहनों का दबाव सबसे अधिक होता है, तब यह खुदाई लोगों के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रही है।

10 हजार करोड़ में इंदौर से उज्जैन का होगा सफर तय

इंदौर। इंदौर और उज्जैन के बीच सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। दोनों धार्मिक और व्यावसायिक शहरों को जोड़ने वाली प्रस्तावित मेट्रो परियोजना अब अपने अगले महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुकी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। यह परियोजना लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तैयार होगी और इसका मुख्य लक्ष्य इंदौर से उज्जैन के बीच यात्रा को सुपरफास्ट और बेहद सुविधाजनक बनाना है। अधिकारियों का मानना है कि इस मेट्रो प्रोजेक्ट से दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, जिससे दैनिक यात्रियों और श्रद्धालुओं को बड़ा लाभ मिलेगा।

विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर इंदौर में निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर 25 को

इंदौर। विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ एवं पशुपालन एवं डेयरी विभाग, इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में 25 अप्रैल 2026, शनिवार को एक निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर पशु चिकित्सालय राज मोहल्ला, एमओजी लाइन, इंदौर में प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगा। शिविर में पशुपालकों एवं पशु प्रेमियों के लिए रेबीज टीकाकरण, पशु स्वास्थ्य परीक्षण, कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण तथा निःशुल्क औषधि वितरण जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

बॉयफ्रेंड ने वीडियो कॉल नहीं उठाया तो मैसेज में लिखा-अब तुम खुश रहना और दे दी जान

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

मध्यप्रदेश के इंदौर में एक 21 वर्षीय युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवती को जब अपने कमरे से काफी देर तक बाहर नहीं आई तो परिजन ने कमरे में झांककर देखा तो वो फांसी पर लटकी नजर आई। परिजन तुरंत युवती को फांसी के फंदे से उतारकर अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि युवती ने सुसाइड करने से पहले अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया था जिसमें उसने लिखा था कि अब तुम खुश रहना। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस ने बताया कि परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के जनता क्वार्टर में रहने वाली नम्रता रूबिन (21 वर्ष) ने घर के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। देर रात जब उसने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खटखटाया तो परिजन ने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। परिजन ने मोबाइल पर फोन किया तो फोन अंदर ही बजता रहा लेकिन नम्रता ने फोन नहीं उठाया। परेशान होकर परिजन ने कमरे में झांका तो नम्रता फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। परिजन उसे फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और पुलिस को सूचना दी।

बॉयफ्रेंड को मैसेज किया- 'अब तुम खुश रहना'

बताया गया है कि खुदकुशी करने से पहले नम्रता ने अपने बॉयफ्रेंड विशाल को वीडियो कॉल किया था लेकिन विशाल ने वीडियो कॉल रिसीव नहीं किया इसके बाद नम्रता ने मैसेज में लिखा अब तुम खुश रहना और फांसी लगा ली। परिजनों के अनुसार नम्रता एक शेयर कंपनी में काम करती थी। उसकी बहन ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही थी। परिवार में नम्रता की दो छोटी बहनें भी हैं। नम्रता के इस तरह से खुदकुशी करने से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और उनका रो-रोकर बुरा हाल है।

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतका का मोबाइल जब्त कर लिया है। पुलिस ने मृतका नम्रता के कमरे में भी छानबीन की लेकिन वहां उसे कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल को जब्त कर उसकी कॉल डिटेल व मैसेज की जांच की जा रही है। मामले में युवक विशाल से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है।

इंदौर की किसान दीदी ने जगाई पराली नहीं जलाने की अलख, 600 बीघा खेत बचाए

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

उत्तर भारत में फसल कटाई के बाद पराली जलाने की समस्या लंबे समय से बनी हुई है लेकिन मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के धुलेट गांव में एक महिला किसान ने इस प्रवृति को बदलने की दिशा में मिसाल पेश की है। गांव की रहने वाली श्रीमती पपीता रावत ने न केवल किसानों को जागरूक किया, बल्कि वैकल्पिक समाधान देकर पराली जलाने पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्रीमती पपीता रावत, जो एक स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष है ने अपनी यात्रा आजीविका मिशन से जुड़कर शुरू की। शुरूआती आर्थिक तंगी के बीच उन्होंने सिलाई कार्य से शुरूआत की। कृषि गतिविधियों में रूचि के चलते बाद में स्व-सहायता समूह और बैंक से ऋण लेकर स्ट्रा

रीपर मशीन खरीदी। इसके बाद उन्होंने गांव और आसपास के किसानों को पराली जलाने के नुकसान और उससे भूसा बनाने के फायदे समझाए। जिले के धुलेट गांव के आसपास दूर-दूर तक कोई भी किसान अब अपने खेत में पराली (गेहूं कटाई के बाद बचे हुए ठूंठ,अवशेष) नहीं जलाता। इसका कारण महिला किसान श्रीमती पपीता रावत है। पपीता रावत बताती है - ₹शुरूआती दिनों में मैं घर ही रहती और मेरे पति महेश मजदूरी करने जाते थे। घर में तंगी बनी रहती।

नन्ही योगीशा का बड़ा संदेश: सड़क सुरक्षा की सीख से सबको किया जागरूक

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

राऊ क्षेत्र में एक सराहनीय पहल सामने आई, जहां एक नन्ही बालिका ने अपनी समझ और जागरूकता से सभी का ध्यान सड़क सुरक्षा की ओर खींचा। स्कूल में आयोजित ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोजेक्ट के दौरान योगीशा शर्मा ने अपने साथियों के बीच बेहद सरल लेकिन प्रभावी तरीके से ट्रैफिक नियमों का महत्व समझाया।

योगीशा ने अपने प्रस्तुतीकरण में बताया कि हेलमेट और सीट बेल्ट केवल नियम नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा से जुड़े जरूरी कदम हैं। उन्होंने बच्चों को यह भी समझाया कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और छोटी-छोटी सावधानियां बड़े हादसों को रोक सकती हैं। कार्यक्रम के दौरान योगीशा का आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच देखने लायक थी। उनकी बातों ने न सिर्फ विद्यार्थियों बल्कि शिक्षकों को भी प्रभावित किया। स्कूल प्रबंधन ने इस पहल को सराहते हुए कहा कि इस

तरह की गतिविधियां बच्चों में जिम्मेदारी और जागरूकता का भाव विकसित करती हैं। आज के दौर में जब सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में एक छोटी बच्ची द्वारा दिया गया यह संदेश समाज के लिए बड़ी सीख बनकर सामने आया है। योगीशा ने यह साबित कर दिया कि बदलाव लाने के लिए उम्र नहीं, सोच मायने रखती है। छोटी उम्र, बड़ा संदेश – सुरक्षित भारत की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम।

गैस सिलेंडर डिलीवरी के समय जरूर चेक करें वजन

इंदौर। गैस सिलेंडरों को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी कम नहीं हो रही है। पहले सिलेंडरों की कालाबाजारी की शिकायतें सामने आईं। खाद्य एवं आपूर्ति प्रशासन विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडर से व्यावसायिक गैस सिलेंडर में अवैध गैस रिफिल के केस भी पकड़े। अब कम वजन वाले गैस सिलेंडर घर पहुंचाए जा रहे हैं। सिलेंडर पूरी तरह पैक था। एक उपभोक्ता ने जब अपने घर पहुंचे सिलेंडर का वजन कराया तो उसमें निर्धारित मात्रा से कम 3 किलो 170 ग्राम एलपीजी कम पाई गई। कई उपभोक्ता बगैर तौल के गैस सिलेंडर ले रहे हैं और कालाबाजारी करने वालों की चालबाजी का शिकार हो रहे हैं। नियमानुसार गैस एजेंसियों को हर उपभोक्ता को सिलेंडर का वजन कर देना होता है।

बैंक सुरक्षा पर कड़ा एक्शन: जोन-4 में हाई लेवल मीटिंग,लापरवाही बर्दाश्त नहीं

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

शहर में बैंक सुरक्षा को लेकर पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। इंदौर पुलिस ने जोन-4 में बैंक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित कर साफ संदेश दे दिया है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक अब बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में पुलिस उपायुक्त आनंद कलादगी और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त दिशेष अग्रवाल के नेतृत्व में जोन-4 के सभी बैंक प्रबंधकों को बुलाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई। अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि हर बैंक को अपने सुरक्षा सिस्टम को अपडेट और एक्टिव रखना अनिवार्य होगा।

सुरक्षा को लेकर दिए गए अहम निर्देश:

- सभी बैंक शाखाओं में सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह चालू और हाई क्वालिटी में रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के निर्देश
- अलार्म सिस्टम और स्ट्रॉन्ग रूम सुरक्षा की नियमित जांच अनिवार्य
- सिक्योरिटी गार्ड की सतत निगरानी और उनकी जिम्मेदारी तय करने के निर्देश
- थाना स्तर पर नियमित निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट लागू करने पर जोर

डकैती से सबक, अब नहीं होगी चूक

हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सिंगरौली शाखा में हुई बैंक डकैती की घटना को गंभीरता से लेते हुए बैठक में सुरक्षा प्रोटोकॉल को और सख्त करने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हर स्तर पर सतर्कता जरूरी है। सख्त चेतावनी पुलिस अधिकारियों ने दो टूक कहा– बैंक सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है। आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि इंदौर पुलिस ने स्पष्ट किया कि बैंकिंग संस्थानों की सुरक्षा सिर्फ संपत्ति की सुरक्षा नहीं, बल्कि आम नागरिकों के विश्वास और सुरक्षा से भी जुड़ी है।

संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर बैठक में

यह भी तय किया गया कि बैंक परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस की नियमित चेकिंग और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा, ताकि किसी भी वारदात की स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके। अधिकारियों ने बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिए कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। साथ ही सूचना साझाकरण प्रणाली को तेज और प्रभावी बनाने पर विशेष बल दिया गया।

उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में 9 मई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में 9 मई 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार किया जा रहा है। प्रशासनिक न्यायाधीश श्री विजय कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर त्वरित निराकरण किया जाएगा। समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से अपील की गई है कि वे अपने लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाएं।

स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डेवलप करने के 7 सूत्र...

फिर भी जिंदगी हसीन है...
dreamsachieverspune@gmail.com

आज के जटिल और तेजी से बदलते समय में केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही दिशा में सोचना और निर्णय लेना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। रणनीतिक सोच याने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एक ऐसी क्षमता है जो व्यक्ति को भीड़ से अलग बनाती है। यह केवल एक कौशल नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका है; इंसान के व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। प्रसिद्ध लेखक और विचारक एलेक्स एम. एच. स्मिथ के अनुसार, रणनीतिक सोच रखने वाले लोग कुछ अनोखे गुणों से पहचाने जाते हैं, जो सामान्य धारणाओं से अलग होते हैं। आइए, आज हम स्मिथ द्वारा बताए गए उन 7 गुणों या सूत्रों पर चर्चा करते हैं-

निर्मल भटनागर (एजुकेशनल कंसलटेंट एवं मोटिवेशनल स्पीकर)
दैनिक ग्लोबल हेराल्ड

1) हर छोटी-छोटी बात में ना उलझना

रणनीतिक सोच रखने वाला व्यक्ति हर विवरण में फंसने के बजाय बड़े चित्र याने अपने विज़न पर ध्यान देता है। वह जानता है कि हर जानकारी जरूरी नहीं होती; उसके लिए तो सही दिशा और सार को पकड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह दृष्टिकोण उसे स्पष्ट और प्रभावी निर्णय लेने में मदद करता है।

2) विपरीत सोच याने कंटेरियन थिंकिंग

ऐसे लोग केवल परंपरागत सोच को स्वीकार नहीं करते, बल्कि सवाल उठाते हैं। वे वही सोचते हैं जो आम लोग नहीं सोचते। यह आदत उन्हें नए दृष्टिकोण और अवसर खोजने में सक्षम बनाती है।

3) क्रियाशीलता याने एक्शन ओरिएंटेड रहना

केवल योजना बनाना पर्याप्त नहीं है। एक सच्चा रणनीतिक व्यक्ति विचारों को कार्य में बदलने पर विश्वास करता है। वह विश्लेषण में उलझने के बजाय परिणामों पर ध्यान देता है।

4) कटु सत्य को स्वीकार करना

रणनीतिक सोच रखने वाले लोग सच्चाई से भागते नहीं हैं, चाहे वह कितनी भी असहज क्यों न हो। वे ईमानदारी से स्थिति का आकलन करते हैं और उसी के आधार पर निर्णय लेते हैं। यही उनकी ताकत होती है।

5) जिम्मेदारी लेना

ऐसे लोग अपने निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। वे असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। यह गुण उन्हें आत्मनिर्भर और विश्वसनीय बनाता है।

6) प्रभावी संवाद और लेखन कौशल

रणनीति केवल सोचने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना भी उतना ही जरूरी है। एक अच्छा रणनीतिक व्यक्ति अपने विचारों को सरल, प्रभावी और प्रेरणादायक तरीके से प्रस्तुत करता है।

7) थोड़ी अपरंपरागत सोच रखना

सबसे रोचक गुण है रणनीतिक व्यक्ति हमेशा पारंपरिक नियमों में बंधकर नहीं चलता। वह नए प्रयोग करने, जोखिम लेने और अलग तरीके से सोचने में विश्वास करता है। यही स्वतंत्र सोच उसे नवाचार याने इनोवेशन की ओर ले जाती है।

अंततः, यह समझना जरूरी है कि ये सभी गुण पारंपरिक रूप से परफेक्ट नहीं माने जाते, लेकिन यही गुण किसी व्यक्ति को असाधारण बनाते हैं। रणनीतिक सोच का अर्थ है—स्पष्टता, साहस और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना। यदि हम इन गुणों को धीरे-धीरे अपने जीवन में अपनाना शुरू करें, तो न केवल हमारे निर्णय बेहतर होंगे, बल्कि हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी एक नई ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। याद रखियेगा, रणनीतिक सोच कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह एक विकसित की जाने वाली आदत है और हर व्यक्ति इसे सीख सकता है।

गौ सम्मान को लेकर देशव्यापी हुंकार, 27 अप्रैल को मनाया जाएगा गो सम्मान दिवस

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

गौ संरक्षण और सम्मान को लेकर देशभर में एक बड़ा अभियान आकार ले रहा है। राजधानी दिल्ली में आयोजित बैठक में संतों, गोभक्तों और गोसेवकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 27 अप्रैल को पूरे देश में गो सम्मान दिवस मनाया जाएगा। यह जानकारी इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में कृष्णायन गोशाला हरिद्वार के अच्युतानंद जी महाराज और गोपालाचार्य गोपालानंद सरस्वती महाराज ने दी।

संतों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान किसी राजनीतिक दल, संस्था या संगठन के बैनर तले नहीं, बल्कि गौमाता और नंदी बाबा के सानिध्य में पूरी तरह अहिंसक और गैर-राजनीतिक रूप से संचालित होगा। इसका उद्देश्य केवल जनजागरण और गौ संरक्षण के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर

मजबूती से उठाना है। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि अभियान के प्रमुख उद्देश्यों में गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना, गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कराना, गोतस्करी रोकने के लिए सख्त कानून बनाना और गोवर्धन संस्कृति के संरक्षण के लिए ठोस सरकारी नीतियां लागू कराना शामिल है। संतों ने मांग रखी कि गौ रक्षा के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाए, दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिले और जब्त किए गए वाहनों को गोशालाओं के उपयोग में लाया जाए। इसके साथ ही गोबर और गोमूत्र आधारित अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करने, पंचगव्य औषधियों का आयुर्वेदिक अस्पतालों में निःशुल्क वितरण करने और सरकारी भवनों में गोबर पेंट व गौनाइल के उपयोग को अनिवार्य बनाने की मांग भी रखी गई। गौशालाओं को मनरेगा से जोड़ने, बिजली बिल में राहत देने और निराश्रित गौवंश के लिए चारे की समुचित व्यवस्था की भी बात कही गई।

10वीं-12वीं की द्वितीय परीक्षा के लिए आवेदन अब 26 अप्रैल तक

इंदौर (ग्लोबल हेराल्ड)। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने गुरुवार को विद्यार्थियों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी द्वितीय परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 26 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में मंडल ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश के सचिव श्री बुद्धेश कुमार वैद्य ने बताया कि विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि को बढ़ा दिया गया है।

जब भेद मिटता है, तो मनुष्य के अंदर एकत्व का भाव जगता है

श्री श्री आनन्दमूर्ति

ग्लोबल हेराल्ड

एक बार एक साधक ने प्रश्न किया, 'बाबा, बार-बार चेतना को को व्यापक करने की बात कही जाती है। चेतना का व्यापक होना क्या है और जब चेतना व्यापक हो जाती है, तो उसका परिणाम क्या आता है, कृपया समझाएं?' आम दृष्टि में संसार अनेकता से भरा दिखाई देता है—व्यक्ति अलग, वस्तुएँ अलग, विचार अलग। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह विविधता एक गहरे एकत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। यही वह बिंदु है जहाँ ब्रह्म का ज्ञाता साधारण व्यक्ति से भिन्न हो जाता है।

एक सामान्य व्यक्ति पानी और बर्फ को अलग-अलग मानता है, जबकि थोड़ी समझ रखने वाला जानता है कि बर्फ, पानी का ही स्थूल रूप है। ठीक इसी प्रकार, जहाँ साधारण बुद्धि व्यक्ति, वस्तु और उनके संबंधों में भेद देखती है—जैसे कुम्हार और घड़ा, धर्म और धार्मिक व्यक्ति—वहीं ब्रह्म का ज्ञाता इन सबमें एक ही चेतना का प्रवाह देखता है। उसके लिए यह संपूर्ण जगत उसी परम सत्ता का विस्तार है। यह प्रश्न कि संसार और ब्रह्म अलग हैं या एक?—एक सीमित दृष्टि का परिणाम है। जब चेतना व्यापक होती है, तो यह प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाता है। ब्रह्म का ज्ञाता अनुभव करता है कि सब कुछ उसी का रूप है—वह स्वयं भी और यह जगत भी। जैसे हमारे मन में लंदन की कल्पना और हमारा मन अलग नहीं होते, वैसे ही यह सारा विश्व ब्रह्म की ही मानसिक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्म का कोई तुल्य या तुलना नहीं है—न तस्य प्रतिमा अस्ति। तुलना तभी संभव है जब दो वस्तुएँ हों, और ब्रह्म अद्वितीय है। वह शब्दों और विचारों की सीमा से परे है, फिर भी उसे अनुभव किया जा सकता है—बौद्धिक तर्क से नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभूति से। इसी संदर्भ में नमक की गुड़िया का उदाहरण अत्यंत सुंदर है। जब एक नमक की गुड़िया समुद्र की गहराई मापने जाती है, तो वह स्वयं समुद्र में विलीन हो जाती है। ठीक वैसे ही, जब साधक ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है, तो वह स्वयं उसी में लीन हो जाता है—ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। यानी ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म और असीम है। वह न तो आँखों से देखा जा सकता है, न ही इंद्रियों से पकड़ा जा सकता है। उसका कोई रूप, आकार या जन्म नहीं है। यदि उसे किसी रूप में बाँध दिया जाए, तो उसकी अनंतता समाप्त हो जाएगी। इसलिए वह निराकार, निरुपम और अनादि है। फिर भी, वह सब कुछ देखता, सुनता और करता है—बिना किसी भौतिक अंगों के। जैसे हम अपने मन में किसी वृक्ष की कल्पना करते हैं और उसका चित्र उभर आता है, वैसे ही ब्रह्म अपनी चेतना से समस्त सृष्टि का संचालन करता है। वह काल, स्थान और व्यक्ति की सीमाओं से परे एक शाश्वत सत्ता है। ब्रह्म सर्वव्यापी है—वह हमारे चारों ओर, हमारे भीतर, हर दिशा में उपस्थित है। उससे अलग कुछ भी नहीं। इसी कारण उसे विभु कहा गया है। वह सृष्टि का कारण भी है और उसका साक्षी भी। जब ब्रह्म अपनी क्रियाशील शक्ति (प्रकृति) के साथ जुड़ता है, तो सृष्टि का विस्तार होता है। इसी से ॐ (ओंकार) की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे सृष्टि की मूल ध्वनि माना गया है। यह ओंकार ही ब्रह्म के सूक्ष्म और स्थूल रूपों के बीच का सेतु है। ब्रह्म के अनेक रूप हैं—वह सृजन करता है तो ब्रह्मा कहलाता है, साक्षी रूप में शिव, पालनकर्ता के रूप में विष्णु, और संहार की शक्ति के रूप में कालाग्नि। वास्तव में ये सभी नाम उसी एक सत्ता के विभिन्न आयाम हैं। इस ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति मृत्यु और भय से परे हो जाता है। वह समझता है कि जो कुछ था, है और होगा—सब उसी में निहित है। यह ज्ञान उसे स्थायी शांति और आनंद की ओर ले जाता है। अंततः, यह अनुभूति केवल बौद्धिक समझ से नहीं, बल्कि साधना और ध्यान से प्राप्त होती है। जब व्यक्ति हर क्षण ईश्वर का स्मरण करता है, अपने भीतर झाँकता है और अपने अहंकार को त्यागता है, तब वह इस सत्य को जीने लगता है।

यही एकत्व का बोध है—जहाँ भेद समाप्त हो जाता है, और केवल ब्रह्म ही शेष रहता है।

प्रस्तुतिः दिव्यचेतनानंद अवधूत

लेंसकार्ट कंपनी की ड्रेस कोड नीति पर बवाल, हिंदू संगठनों ने शोरूम के बाहर तोड़े चश्मे

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

लेंसकार्ट की ड्रेस कोड नीति को लेकर उपजा विवाद अब सड़कों पर उतर आया है। इंदौर में वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन मध्य प्रदेश के बैनर तले संगठन के कार्यकताओं ने कंपनी के शोरूम के बाहर एकत्रित होकर उग्र प्रदर्शन किया और कंपनी के उत्पादों के पूर्ण बहिष्कार का ऐलान कर दिया।

स्कीम-54 स्थित शोरूम के सामने आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पुरुष और महिला कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकताओं ने वहां कार्यरत महिला कर्मचारियों को तिलक लगाया और उन्हें आश्वस्त किया कि वे बिना किसी संकोच या डर के अपने धार्मिक प्रतीकों के साथ कार्यस्थल पर जा सकती हैं। विरोध के स्वरूप कुछ प्रदर्शनकारियों ने कंपनी के चश्मों को तोड़कर अपना रोष प्रकट किया। इस अवसर पर सिद्धेश्वर धाम के पीठाधीश्वर स्वामी अतुल आनंद महाराज भी उपस्थित रहे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कंपनी पर आरोप लगाया कि उनकी आंतरिक नीति में बिंदी, तिलक और कलावा जैसे हिंदू प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि हिजाब के उपयोग की अनुमति दी गई है। उन्होंने इस स्थिति को धार्मिक भेदभाव का स्पष्ट उदाहरण बताया।

धार्मिक भेदभाव के आरोपों पर संगठन का कड़ा रुख

संजय अग्रवाल ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि किसी भी संस्थान में एक धर्म विशेष के प्रतीकों को अनुमति देना और दूसरों पर रोक लगाना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भेदभावपूर्ण नीतियां किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएंगी। संगठन ने गुरुवार को इंदौर के सभी केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही पूरे प्रदेश में कंपनी के बहिष्कार का आह्वान किया है। फेडरेशन की महिला प्रदेश अध्यक्ष सुनीता जायसवाल और अन्य महिला कार्यकताओं ने भी नीति के विरुद्ध मोर्चा खोला और चेतावनी दी कि यदि कंपनी ने अपने नियमों में स्थायी सुधार नहीं किया तो आने वाले समय में आंदोलन को और अधिक उग्र रूप दिया जाएगा।

कंपनी प्रबंधन और सीईओ की ओर से दी गई सफाई

विवाद के राष्ट्रव्यापी स्तर पर पहुंचने के बाद कंपनी के संस्थापक और सीईओ पीयूष बंसल ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो दस्तावेज प्रसारित हो रहे हैं वे पुराने हैं और वर्तमान में कंपनी की ऐसी कोई मंशा नहीं है। नई नीति के हवाले से कंपनी ने साफ किया कि अब बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, हिजाब और पगड़ी जैसे सभी धार्मिक व सांस्कृतिक प्रतीकों को पहनने की पूरी स्वतंत्रता है। प्रबंधन ने इस पूरे घटनाक्रम से पैदा हुए भ्रम और विवाद के लिए खेद भी प्रकट किया है।

सार्वजनिक माफी की मांग

हालांकि कंपनी की सफाई के बावजूद फेडरेशन अपने रुख पर अडिग है। संगठन का मानना है कि शुरूआती नीति में जो भेदभाव देखा गया, उसके लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए। संगठन ने मांग की है कि कंपनी को इस विषय पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और भविष्य में ऐसी किसी भी भेदभावपूर्ण नीति को लागू न करने की लिखित गारंटी देनी चाहिए।

भोजशाला सर्वे की वीडियोग्राफी सभी पक्षकारों को देनी होगी

कोर्ट ने कहा- 27 तक मुहैया कराएं

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

धार भोजशाला मामले में अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को मुस्लिम पक्ष सहित अन्य पक्षकारों को सर्वे की वीडियोग्राफी मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल तक सभी पक्षों को वीडियो क्लिप्स उपलब्ध कराने को कहा है।

एएसआई की तरफ से यह भी कहा गया कि इतने फुटेज उपलब्ध कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि सर्वे 98 दिनों तक चला है और हर दिन की वीडियोग्राफी की गई है। कोर्ट ने कहा कि तकनीकी माध्यमों के जरिए इसे उपलब्ध कराया जाए। धार स्थित भोजशाला मामले में नियमित सुनवाई चल रही है। दो पक्षकारों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा एएसआई को भी पक्ष रखने का मौका दिया गया। अब मुस्लिम पक्ष ने अपने तर्क रखे हैं और फिर वीडियोग्राफी की पुरानी मांग दोहराई है। हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को आदेश दिया है कि भोजशाला में किए गए सर्वे की पूरी वीडियोग्राफी सभी पक्षों को उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने कहा है कि 27 अप्रैल तक हर हाल में वीडियो क्लिप्स संबंधित पक्षों को दी जाएं, ताकि वे इन वीडियो के आधार पर अपने तर्क पेश कर सकें। जब भोजशाला मामले में सुनवाई हुई थी, तब मुस्लिम पक्ष की तरफ से सर्वे की वीडियोग्राफी मुहैया कराने की मांग की गई थी। इसके अलावा इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण भी ली गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब सुनवाई के दौरान फिर मुस्लिम पक्ष ने यह मांग दोहराई, तो कोर्ट ने सभी पक्षकारों को वीडियो फुटेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

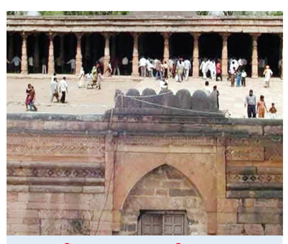

धार में स्थित भोजशाला

इस आदेश के बाद आने वाली सुनवाई में वीडियो फुटेज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसी आधार पर दोनों पक्ष अपने दावे और तर्क मजबूत करेंगे।आपको बता दें कि 98 दिनों तक एएसआई ने भोजशाला में अलग-अलग तकनीकों से सर्वे किया है और 2000 पेज से अधिक की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में खुदाई में मिले अवशेष और उन पर अंकित चित्रों के फोटो भी शामिल किए गए हैं।

विकास कार्यों की प्रगति का लिया जायजा

इंदौर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सिद्धार्थ जैन द्वारा आज जनपद पंचायत सांवेर कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालयीन व्यवस्थाओं, संचालित शासकीय योजनाओं एवं उनकी प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। श्री जैन ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा पात्र हितग्राहियों को समय-सीमा में लाभ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अभिलेखों का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए उनके समुचित संधारण, कार्यों की गुणवत्ता एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्णता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत हासाखेड़ी में नवीन निर्मित अटल सुशासन भवन (ग्राम पंचायत भवन) का अवलोकन किया गया।

कारगिल से कन्या कुमारी तक दौड़ेंगे इंदौर के धावक कार्तिक

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

इंदौर के अल्ट्रा रनर कार्तिक जोशी एक और रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वे कारगिल से कन्याकुमारी तक 4200 किलोमीटर की यात्रा दौड़कर पूरी करेंगे। कार्तिक 50 दिनों तक हर दिन 84 किलोमीटर दौड़कर अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। 28 अप्रैल से वे अपनी दौड़ शुरू करेंगे। इसके लिए कार्तिक इंदौर से कारगिल के लिए रवाना हो चुके हैं।

वे 50 दिनों तक रोज करीब 84 किलोमीटर दौड़ते हुए कुल 4200 किलोमीटर की दूरी तय कर कारगिल से कन्याकुमारी तक जून माह के अंत तक पहुँचेंगे। यह कारनामा करने वाले वे सबसे कम उम्र के भारतीय धावकों में से एक होंगे। कार्तिक को इस दौड़ को पूरा करने के लिए अलग-अलग मौसमों का भी सामना करना होगा। कारगिल के बर्फीले इलाकों से दौड़ शुरू करेंगे, लेकिन कन्याकुमारी तक आते-आते उन्हें कई गर्म इलाकों से भी गुजरना होगा। पहाड़ी रास्तों, मैदानी सड़कों और समुद्री इलाकों के बीच से दौड़कर कार्तिक अपनी यात्रा पूरी करेंगे। कारगिल से श्रीनगर के बीच धावक को जोजिला दर्रा पार करना होगा, जिसकी ऊँचाई करीब 11,600 फीट है। इस हिस्से में ऑक्सीजन कम होती है, तेज ठंडी हवाएँ चलती हैं और पहाड़ों की सीधी चढ़ाई इस दौड़ को बेहद मुश्किल बना देती है।

विधायक उषा ठाकुर ने प्रीतम लोधी मामले में कहा- चाहे कोई भी व्यक्ति हो, पार्टी कठोर कार्रवाई करेगी

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

विधायक प्रीतम लोधी के बेटे द्वारा किए गए एक्सीडेंट और उसके बाद आए विधायक लोधी के विवादित बयान को लेकर विधायक व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उषा ठाकुर ने कहा कि प्रकरण भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के संज्ञान में है। पार्टी इस मामले में कोई कोताही नहीं बरत रही है। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। भाजपा अपनी पंच निष्ठाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। इस मामले में कठोरतम कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो।

महू क्षेत्र में महिला अपराधों के बढ़ते मामले सामने आने पर ठाकुर ने कहा कि प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। समाज को भी जागरूक और संस्कारित होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कठोर कार्रवाई हो रही है। इसके बावजूद अपराधी डर नहीं रहे हैं, तो समाज को इसे रोकने के प्रयास करने होंगे। नशे और संस्कारहीनता के कारण इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं।

इंदौर के किसानों को होगा ज्यादा फायदा

प्रदेश सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए ली जाने वाली किसानों की जमीन के एवज में कलेक्टर गाइडलाइन से चार गुना मुआवजा देने के फैसले पर भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने कहा कि इंदौर में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहा है। इसके अलावा बुधनी रेल लाइन सहित अन्य प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। जिन गांवों में जमीन अधिग्रहण के अवॉर्ड पारित नहीं हुए हैं, वहां इस फैसले का फायदा किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि चार गुना जमीन की कीमत मिलने पर किसान भी आसानी से विकास कार्यों के लिए जमीन देने के लिए तैयार हो जाएंगे।

इंदौर में बाल श्रम उन्मूलन व बंधक श्रम रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 तथा बंधक श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं जिला स्तरीय समिति की संयुक्त बैठक का आयोजन जिला पंचायत सभागृह, इंदौर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, श्री सिद्धार्थ जैन द्वारा की गई।

बैठक में सहायक श्रमायुक्त श्रीमती राखी जोशी ने वर्ष 2025-26 के दौरान जिले में बाल श्रम एवं बंधक श्रम से संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत की गई कार्यवाहियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों के समन्वित प्रयासों से इन मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बैठक में पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण समिति, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चाइल्ड लाइन के सदस्य उपस्थित रहे। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जैन ने बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में बाल श्रम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बैंक कर्मचारी बनकर ठगों ने बिछाया जाल आईटी इंजीनियर के 4.73 लाख लूटे

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

इंदौर में साइबर अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामले में शहर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जालसाजों ने अपना निशाना बनाया है। टीसीएस कंपनी में कार्यरत इंजीनियर से ठगों ने क्रेडिट कार्ड सक्रिय करने और ट्रांजेक्शन रिवर्स करने के नाम पर करीब 4 लाख 73 हजार रुपए की बड़ी राशि हड़प ली है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना की शुरूआत 7 अप्रैल को हुई जब पीड़ित आभास हिंगे के पास एक अज्ञात नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को एक्सेस बैंक का कर्मचारी बताया और पीड़ित को नया क्रेडिट कार्ड जारी करने का झांसा दिया। बातचीत के दौरान आरोपी ने पीड़ित से उनके मोबाइल पर आया ओटीपी मांगा। शुरूआत में आभास ने सुरक्षा कारणों से ओटीपी देने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद फोन कट गया। हालांकि, कुछ ही देर बाद उनके मोबाइल पर खाते से 1 लाख रुपए कटने का संदेश प्राप्त हुआ जिससे वे हतप्रभ रह गए। पहली राशि कटने के तुरंत बाद पीड़ित के पास दूसरे नंबर से कॉल आया। इस बार फोन करने वाले ने खुद को एचडीएफसी बैंक का कर्मचारी बताते हुए कटे हुए पैसों के बारे में पूछताछ की। जालसाज ने विश्वास में लेने के लिए पीड़ित को एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ा। इस दौरान खुद को बैंक अधिकारी बताने वाले दूसरे व्यक्ति ने दावा किया कि कटे हुए पैसे वापस यानी रिवर्स करने के लिए ओटीपी की आवश्यकता होगी। जैसे ही पीड़ित ने प्रक्रिया के नाम पर ओटीपी साझा किया, उनके खाते से दोबारा पैसे कट गए और कॉल काट दिया गया। ठगों ने अपनी प्रक्रिया पूरी करने के बहाने एक बार फिर कॉल किया और एक और ओटीपी प्राप्त कर लिया। इस तरह किश्तों में कुल 4 लाख 73 हजार रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। जब आभास को ठगी का एहसास हुआ, तो उन्होंने बिना देरी किए साइबर हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। अन्नपूर्णा पुलिस ने दो संदिग्ध मोबाइल नंबर धारकों के खिलाफ बुधवार को एफआईआर दर्ज की है।

9 आरोपियों को किया गया जिलाबदर

इंदौर। इंदौर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त 9 आरोपियों को जिलाबदर किया है। इस संबंध में जारी आदेशानुसार आरोपियों को छः-छः माह के लिये जिलाबदर किया गया है। उक्त सभी अपराधियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनेक अपराधिक प्रकरण दर्ज है। जिला बदर आरोपियों में मानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गिट्टी फोड़ा निवासी धर्मपाल उर्फ धनपाल पिता देवकरण सिंगारे, ग्राम खुर्दा निवासी रितिक पिता घनश्याम जयसवाल, ग्राम अम्बाड़ा सागलाखली निवासी जमनालाल पिता नारायण कटारे, ग्राम गोलखेड़ा निवासी सारंग पिता बोंदर गावड़, किसान मोहल्ला निवासी पम्मी उर्फ निजीत्व पिता परसराम जाट और बसौड़ मोहल्ला निवासी अभि उर्फ अभिषेक पिता अशोक मेढ़ा सम्मिलित है।

मेट्रो ट्रेक के डिवाइडर से हटाए अवैध होर्डिंग एमआईसी मेंबर राठौर ने ली थी आपत्ति

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

इंदौर में विजय नगर के समीप मेट्रो ट्रैक के डिवाइडर के नीचे अवैध रूप से एक एजेंसी द्वारा होर्डिंग लगा दिए गए थे। इसके लिए न तो नगर निगम ने टेंडर जारी किए थे और न ही किसी प्रकार की अनुमति दी गई थी। बुधवार को इन अवैध होडिंगों को जमीन से उखाड़ दिया गया। इनकी संख्या 30 से अधिक थी।

शहर के पॉश इलाके सयाजी से विजय नगर और रेडिसन चौराहा के बीच मेट्रो डिवाइडर पर पिछले माह ये होर्डिंग लगाए गए थे। एमआईसी मेंबर राजेंद्र राठौर ने इसे विज्ञापन घोटाला करार देते हुए मौके पर जाकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से ये होर्डिंग लगाए गए हैं और इससे नगर निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है। यदि टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से इस महंगे रूट पर डिवाइडर लगाए जाते, तो नगर निगम को अधिक राजस्व प्राप्त होता। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई और अधिकारियों ने स्वीकार किया कि ये होर्डिंग नगर निगम की अनुमति के बिना लगाए गए थे। इस प्रकार डिवाइडरों पर होर्डिंग लगाना हाईकोर्ट ने भी उचित नहीं माना है। इसके बाद गुरुवार को नगर निगम की रिमूवल टीम ने इन अवैध होडिंगों को हटा दिया। इंदौर में अवैध होडिंगों की संख्या काफी अधिक है। समय-समय पर इन्हें हटाने की बात तो होती है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी ठोस कार्रवाई नहीं करते। सालभर पहले भी नगर निगम के एक अन्य एमआईसी मेंबर ने चौराहों पर लगे होर्डिंग के स्ट्रक्चर को स्वयं मौके पर जाकर हटाया था। उस समय भी यह मुद्दा काफी चर्चा में रहा था।

नई रेल लाइन का सफल ट्रायल, महाराष्ट्र तक बढ़ेगी कनेक्टिविटी, 135 की स्पीड से दौड़ी ट्रेन

बुरहानपुर ■

मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पश्चिम रेल्वे के अंतर्गत एक नए रेलवे रूट का ट्रायल किया गया है। दरअसल, महू-अकोला रेल्वे रूट पर ब्रॉडगेज लाइन कन्वर्जन का लंबे समय से चल रहा है। इसी के अंतर्गत गुरुवार को बुरहानपुर जिले के अमुल्ला खुर्द से तुकईथड़ तक रेलवे रूट का सीआरएस द्वारा ट्रॉयल किया गया जो पूरी तरह सफल रहा। इस ट्रॉयल में रेल (ट्रेन) 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई गई। इससे पहले खंडवा से तुकईथड़ गांव तक के रूट का कार्य पूरा हो चुका है। जानकारी के लिए बता दें कि,यह खंडवा-अकोला ब्रॉडगेज कन्वर्जन परियोजना का हिस्सा है। इसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

मिली जानकारी के अनुसार, इस ट्रॉयल की तैयारियां पिछले 8 दिनों से चल रही थी। इसके लिए तुकईथड़, रत्नापुर, अमूल्ला खुर्द रेल्वे स्टेशन को भव्य तरीके से सजाया गया था। इस ट्रॉयल से समस्त रेलवे अधिकारियों कर्मचारियों जिन ठेकेदारों ने इस रेल्वे ट्रैक को तैयार किया है सभी में एक खुशी की लहर देखने को मिली। इस ट्रॉयल में सीआरएस अधिकारी, डीआरएम नांदेड़, सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

सबसे बड़ा सवाल- कब शुरू होगी ट्रेन सेवा

रेलवे रूट का साफा ट्रायल होने के बावजूद अभी रेलवे अधिकारियों ने साफ नहीं किया है कि यहां ट्रेन सेवा किस तारीख से शुरू की जाएगी। बता दें कि, क्षेत्र के लोग पिछले 10 सालों से इसका इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या इस सफल सीआरएस ट्रायल होने के बाद भी रेल्वे अधिकारी जल्दी इस रूट पर रेल गाड़ी चलाने के लिए हरि झंडी दिखाएंगे या सिर्फ इस सफल ट्रायल लेने के बाद भी क्षेत्र वासियों को और इंतजार करवाएंगे।

तारीख बता पाना मुश्किल- डीआरएम नांदेड़

डीआरएम नांदेड़ डिविजन संदीप पांडे ने बातचीत में बताया है कि आज अमुल्ला खुर्द से ग्राम तुकईथड़ रेल्वे रूट का सीआरएस ट्रायल सफल रहा। इसमें अभी भी कुछ कमियां मिली है जिन्हें पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पांडे ने कहा कि हालांकि अभी यह कहना मुश्किल है इस रूट पर रेल गाड़ी कब तक चालू होगी। अमुल्ला खुर्द से तुकईथड़ ब्रॉडगेज कन्वर्जन परियोजना खंडवा-अकोला रेलवे ट्रैक के आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

पति नहीं, उसके साथ रहूंगी...

विदिशा। मप्र के विदिशा जिले में रिश्तों के बदलते स्वरूप और सामाजिक ताने-बाने को चुनौती देने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस प्रशासन को भी हैरत में डाल दिया है। दो विवाहित महिलाएं एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने की जिद पर अड़ी हैं। इससे उपजा विवाद अब थाने की दहलीज तक जा पहुंचा है। इस उलझे हुए रिश्ते की कहानी तब उजागर हुई जब एक पीड़ित पति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी पत्नी से तलाक दिलाने और दूसरी महिला के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। बीते दिन जनसुनवाई के दौरान एएसपी डॉ. प्रशांत चौबे के पास आवेदकों की लंबी कतार थी। अपनी बारी का इंतजार कर रहे एक युवक का आवेदन जब अधिकारी के हाथ में पहुंचा, तो वे भी चौंक गए। युवक ने अपनी पत्नी के किसी और पुरुष के साथ नहीं, बल्कि एक अन्य विवाहित महिला के साथ समलैंगिक संबंधों का हवाला देते हुए सुरक्षा और न्याय की मांग की थी।

यूपी के व्यापारी की शिकायत पर एमपी में लोकायुक्त ने पकड़ा रिश्वतखोर

टीकमगढ़ ■

मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में गुरुवार को लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते हुए एक वन रक्षक को रंगेहाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर वन रक्षक उत्तर प्रदेश के ललितपुर के रहने वाले एक लकड़ी के व्यापारी से रिश्वत के तौर पर हर महीने 10 हजार रुपये की मांग कर रहा था। जिसकी शिकायत व्यापारी ने सागर लोकायुक्त कार्यालय में की थी और लोकायुक्त की टीम ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए वन रक्षक को रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा है।

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के भानपुर निवासी शिकायतकर्ता अरबाज खान ने बताया कि वह बानपुर में लकड़ी के तख्त, कुर्सी आदि बनाने का काम करता है। इसके लिए वह किसानों से लकड़ी खरीदता है। इस लकड़ी को भानपुर ले जाने के लिए कुंडेश्वर बीट के वनरक्षक अरुण अहिरवार ने उससे प्रति माह 10 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। रुपए न देने पर कार्रवाई करने का डर दिखाते हुए पिछली बार उसका लकड़ी से भरा वाहन जब्त कर लिया था। इतना ही नहीं जब्त वाहन को छोड़ने के एवज में भी उससे 10 हजार रुपये की मांग कर रहा है। लोकायुक्त सागर की टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर गुरुवार को रिश्वत के 5 हजार रुपये देने के लिए आवेदक अरबाज खान को रिश्वतखोर वन रक्षक अरुण अहिरवार के पास भेजा। वन रक्षक अरुण अहिरवार ने रिश्वत देने के लिए फरियादी अरबाज खान को अंबेडकर चौराहे पर वन विभाग के पुराने ऑफिस के पास बुलाया। यहां पर जैसे ही वनरक्षक अरुण अहिरवार ने रिश्वत के 5 हजार रुपये लिए तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक, आरोपी वनरक्षक लंबे समय से वाहन चालकों और छोटे व्यापारियों से अवैध वसूली कर रहा था।

दिल्ली में तबाही का प्लान फेल! ब्लास्ट से पहले पकड़े गए 2 फिदायीन, चौंकाने वाला कनेक्शन

ग्वालियर ■

सोशल मीडिया पर बंदूक की हनक दिखाने और रील बनाकर रंगबाजी करने का शौक ग्वालियर के दो युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों की तरफ ले गया। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने डबरा के इन रीलबाजों को अपना शूटर बनाकर भारत में आतंक फैलाने का जिम्मा सौंपा था।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों के संयुक्त ऑपरेशन में इस खतरनाक मॉडयूल का भंडाफोड़ हुआ है। पकड़े गए युवकों ने जो खुलासे किए हैं, उसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। पाक एजेंसी आइएसआइ के इशारे पर काम करने वाला भट्टी गैंग अब सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं का ब्रेनवाश कर उन्हें हाइब्रिड शूटर बना रहा है।

पति ने नाबालिग गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर पत्नी को मारा फिर पेड़ पर लटका दिया, मामले में बड़ा खुलासा

अनूपपुर ■

मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां लव ट्रायंगल संबंध में हुई महिला की अंधी हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा पदार्फाश किया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि महिला की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति है। हैरानी वाली बात ये है कि आरोपी ने ये हत्या की साजिश अपनी नाबालिग प्रेमिका और एक अन्य नाबालिगके साथ मिलकर रची थी। पुलिस ने बताई पूरी कहानी।

दरअसल, अनूपपुर जिले के वेंकटनगर पुलिस चौकी ने एक अंधी हत्या के मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। त्रिकोणीय प्रेम संबंध के चलते पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार, 15 अप्रैल को ग्राम सिंघौरा निवासी शैलेष कुमार महरा (24) ने अपनी पत्नी गुड़िया महरा के निगौरा रेलवे स्टेशन से लापता होने की रिपोर्ट चौकी वेंकटनगर में दर्ज कराई थी। पुलिस ने महिला को तलाश शुरू की।

पति ने बताया सच, नाबालिग गर्लफ्रेंड ने भी दिया साथ

आरोपी पति ने ने बताया कि 14 अप्रैल की सुबह उसने अपनी नाबालिग प्रेमिका और एक अन्य नाबालिग साथी के साथ मिलकर पत्नी का दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद तीनों ने मिलकर शव को पेड़ पर लटका दिया, ताकि मामला आत्महत्या प्रतीत हो। पुलिस ने मुख्य आरोपी शैलेष महरा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वहीं, नाबालिग प्रेमिका और 17 वर्षीय साथी को बाल न्यायालय में प्रस्तुत कर उन्हें क्रमशः शहडोल और रीवा के सम्प्रेक्षण गृह भेजा गया है।

पेड़ से लटका मिला महिला का शव

पुलिस को जांच के दौरान 18 अप्रैल को उमरिया बीट के जंगल क्षेत्र (बीट क्रमांक 313) में सिद्धबाबा मंदिर की पहाड़ी के पीछे एक महिला का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान गुड़िया महरा के रूप में की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हत्या होना सामने आया, जिसके बाद थाना जैतहरी में मामला दर्ज किया गया।

परिजनों ने खोली पति को पोल- पुलिस ने जांच के दौरान मृतका के परिजनों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस को चौंका देने वाली जानकारी मिली। पुलिस को पता चला कि उसे आखिरी बार मृतिका को उसके पति शैलेष और उसकी नाबालिग प्रेमिका के साथ देखा गया था। पुलिस ने संदेह के आधार पर शैलेष को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया।

48 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ेगी गर्मी

भोपाल। गर्मी से मामूली राहत के बाद एक बाद फिर सूरज के अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। राजधानी में बुधवार को अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री दर्ज किया गया। यह मंगलवार के मुकाबले एक डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वोत्तर से गर्म हवाएं आ रही हैं। जिससे लू का खतरा है। यह सीजन का तीसरा सबसे गर्म दिन रहा है। नर्मदापुरम और खजुराहो सबसे गर्म रहा है। यहां अधिकतम तापमान 43 रिकॉर्ड किया गया है। अगले 48 घंटे में टूट सकते हैं गर्मी के रिकार्डः मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले 48 घंटों में इस सीजन में गर्मी के रिकॉर्ड टूट सकते हैं। शहर का पारा 42 डिग्री के पास जा सकता है। राजस्थान की ओर से आ रही गर्म और शुष्क हवाओं के कारण वातावरण की नमी खत्म हो गई है। इससे लू के हालात बनेंगे। अभी 20 अप्रैल को सीजन का सबसे गर्म दिन 41.8 रहा है।

नीमच में शादी की खुशियां मातम में बदलीं: तलवारों से किया सगे भाइयों पर जानलेवा हमला, पुलिस पर लगा गंभीर आरोप

नीमच ■

नीमच जिले के जीरन थाना क्षेत्र के ग्राम जेतपुरा पालसोड़ा में शादी समारोह की खुशियां अचानक उस समय खूनी संघर्ष में बदल गईं, जब एक बिंदौली के दौरान दो सगे भाइयों को तलवार और पत्थरों से निशाना बनाया गया। घटना के बाद से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित परिवार और नायक रघुवंशी समाज ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए एसपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाया है।

मिली जानकारी के अनुसार, 20 अप्रैल की रात करीब 10 बजे गांव में बिंदौली (वर यात्रा) निकाली जा रही थी। इसी दौरान शिव मंदिर के समीप महेंद्र रावत, गोविंद रावत, प्रभुसिंह, हिम्मतसिंह, ओमसिंह, जीवन और नारायण रावत सहित 10-15 लोगों ने एक राय होकर विशाल नायक को घेर लिया और जबरन घसीटते हुए मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर जब विशाल का भाई नरेंद्र नायक उसे बचाने पहुंचा, तो हमलावरों ने उस पर भी तलवार और पत्थरों से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। गुरुवार को नायक रघुवंशी समाज के लोग लामबंद होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसपी अंकित जायसवाल के नाम डीएसपी निकिता सिंह को ज्ञापन सौंपा। समाजजनों का आरोप है कि घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने न केवल कार्रवाई में देरी की, बल्कि मामले को रफा-दफा करने के लिए हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।आरोप यह भी है कि नामजद रिपोर्ट के बावजूद पुलिस ने आरोपियों की पूरी सूची के बजाय केवल तीन लोगों को ही नामजद किया, जबकि घटना में 10 से 15 लोग शामिल थे। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी प्रभावशाली हैं और राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस सख्त कार्रवाई करने से कतरा रही है।

आरोपियों की धमकी, आर्मी में हूं, गोली मार दूंगा

पीड़ित परिवार ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। परिवार का कहना है कि आरोपी पक्ष लगातार दबाव बना रहा है। उन्हें जान से मारने और घर में आग लगाने की धमकियां दी जा रही हैं। हद तो तब हो गई जब एक आरोपी ने स्वयं को सेना (आर्मी) का जवान बताते हुए परिवार को गोली मारने की धमकी दी।

मृत लोगों को जिंदा बता ली पॉलिसी फर्जी बीमा से आठ करोड़ हड़पे

भोपाल ■

मध्य प्रदेश में बीमा धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (एडह) ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ करीब 8 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में बीमा एजेंटों, पॉलिसीधारकों के नामांकित व्यक्तियों (नॉमिनी) और कुछ लोकसेवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू मुख्यालय भोपाल में दर्ज शिकायत के अनुसार, मंदसौर और उज्जैन क्षेत्र में कई लोगों ने सुनियोजित तरीके से बीमा कंपनी को चूना लगाने की साजिश रची। जांच में सामने आया कि गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों और पहले से मृत व्यक्तियों के नाम पर बीमा पॉलिसियां जारी कराई गईं। बाद में उनके नाम पर फर्जी दस्तावेज लगाकर बीमा क्लेम किया गया।

फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराएं

शिकायत के सत्यापन के दौरान पता चला कि कई मामलों में मृत व्यक्तियों को जीवित बताकर उनके नाम से पॉलिसी ली गई। इसके बाद उनकी मौत दशार्ते हुए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेज तैयार किए गए और बीमा राशि हासिल करने की कोशिश की गई। ईओडब्ल्यू जांच में यह भी सामने आया कि इस पूरे फजीर्वाड़े में कुछ पंचायत कर्मियों और लोकसेवकों की भूमिका भी संदिग्ध रही। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी दस्तावेजों को वैध दिखाने में मदद की। इनमें कुछ सरपंच, सचिव और सहायक सचिवों के नाम भी सामने आए हैं। जांच में कुल 27 बीमा पॉलिसियों की पड़ताल की गई। इनमें से 19 मामलों में गंभीर बीमारी की जानकारी छिपाकर पॉलिसी ली गई, जबकि 8 मामलों में मृत व्यक्तियों के नाम पर बीमा करवाकर क्लेम की कोशिश की गई।

बंगाल की बिसात पर योगी की 'हिंदुत्व' वाली गर्जना...

पश्चिम बंगाल की राजनीति के केंद्र में इस समय केवल चुनावी आंकड़े नहीं, बल्कि विचारधाराओं का वह प्रचंड टकराव है जिसने भारतीय राजनीति के दो ध्रुवों को बिल्कुल आमने-सामने खड़ा कर दिया है। एक ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो भगवा चोले में हिंदुत्व की धार और 'बुलडोजर मॉडल' की धमक लेकर बंगाल की गलियों में टीएमसी के किले को ढहाने निकले हैं, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने इस चुनावी शोर से एक सोची-समझी दूरी बना रखी है। यह दूरी महज संयोग नहीं, बल्कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव और दिल्ली की गद्दी के लिए बुनी जा रही उस बिसात का हिस्सा है, जहां हर कदम फूंक-फूंक कर रखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का बंगाल में उतरना महज एक स्टार प्रचारक की मौजूदगी नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और राजनीतिक संदेश है जो सीधे लखनऊ के गलियारों तक पहुंच रहा है।

अजय कुमार
लेखक
ग्लोबल हेराल्ड

योगी आदित्यनाथ जब पुरुलिया या कोलकाता की सड़कों पर गरजते हैं, तो उनके निशाने पर सिर्फ ममता बनर्जी नहीं होतीं, बल्कि वह तुष्टिकरण की उस राजनीति पर प्रहार करते हैं जिसे भाजपा बंगाल में अपनी जीत की कुंजी मानती है। योगी का 'स्ट्राइक रेट' अब सिर्फ चर्चा का विषय नहीं, बल्कि विपक्षी खेमे के लिए सिरदर्द बन चुका है। बिहार चुनाव में 90 फीसदी और दिल्ली में करीब 78 फीसदी की सफलता दर ने उन्हें भाजपा का सबसे बड़ा 'इम्पैक्ट मेकर' बना दिया है। वह बंगाल की धरती पर खड़े होकर जब यह कहते हैं कि 'बंगाल की पहचान काबा से नहीं, मां कालीबाड़ी से है', तो वह दरअसल बंगाली अस्मिता को हिंदुत्व के साथ जोड़कर एक नया नैरेटिव सेट कर रहे होते हैं। उनका सीधा हमला कोलकाता के मेयर के उस बयान पर है जिसमें उर्दू की वकालत की गई थी। योगी यहां स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि बंगाल में केवल बंगाली और भारतीय संस्कृति चलेगी, किसी भी प्रकार का विदेशी प्रभाव या तुष्टिकरण स्वीकार्य नहीं होगा। दूसरी ओर, अखिलेश यादव की खामोशी उत्तर प्रदेश की राजनीति के भविष्य की ओर इशारा करती है। बंगाल में ममता बनर्जी और अखिलेश के संबंध जगजाहिर हैं। ममता ने यूपी चुनाव में अखिलेश के लिए रैलियां कीं, लेकिन आज जब बंगाल में ममता को उनकी जरूरत थी, तब अखिलेश ने खुद को पीछे खींच लिया। इसके पीछे 'गठबंधन धर्म' का पेचीदा गणित है। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ हैं और टीएमसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। यूपी में अखिलेश और कांग्रेस का अटूट साथ है। अगर अखिलेश बंगाल में ममता के मंच पर जाते, तो यूपी में कांग्रेस के साथ उनके रिश्तों में दरार आ सकती थी। भाजपा को यह कहने का मौका मिल जाता कि अखिलेश 'दो नावों की सवारी' कर रहे हैं। साथ ही,

बंगाल में जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति चरम पर है, अखिलेश नहीं चाहते कि वह ममता के साथ खड़े होकर 'मुस्लिम तुष्टिकरण' के उन आरोपों को खुद पर ओढ़ लें, जिससे वह यूपी में 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के जरिए बचने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का 'यूपी मॉडल' बंगाल में एक ब्रांड बन चुका है। वह अपनी रैलियों में बार-बार 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश की तुलना करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे कभी यूपी में माफियाओं का राज था, कैसे सड़कों पर नमाज के नाम पर अराजकता होती थी और कैसे त्योहारों पर पाबंदियां थीं। उनका 'नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा' का नारा बंगाल के उन मतदाताओं को आकर्षित कर रहा है जो कानून-व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। योगी का बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि सुशासन का प्रतीक बन चुका है, जिसे वह बंगाल में टीएमसी के 'गुंडाराज' के खिलाफ एक हथियार के तौर पर पेश कर रहे हैं। वह टीएमसी कार्यकताओं को चेतावनी देते हैं कि भाजपा की सरकार बनते ही अपराधी जेल में होंगे, ठीक वैसे ही जैसे यूपी के माफिया आज बिलों में छिपे हैं या जेल की सलाखों के पीछे हैं। अखिलेश यादव के लिए चुनौती सिर्फ गठबंधन बचाने की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को बरकरार रखने की भी है। लोकसभा चुनाव में तीसरी बड़ी पार्टी बनने के बाद अखिलेश को भविष्य के पीएम चेहरे के तौर पर देखा जाने लगा है। लेकिन बिहार और अब बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के चुनावों से उनकी अनुपस्थिति उनके 'नेशनल एंबिशन' पर सवाल खड़े करती है। क्या वह केवल यूपी के नेता बनकर रह जाना चाहते हैं? या फिर वह हिंदुत्व बनाम तुष्टिकरण की इस जंग में खुद को इतना सुरक्षित रखना चाहते हैं कि यूपी के बहुसंख्यक वोटों में कोई बिखराव न हो? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव इस समय भाजपा के 'सांप्रदायिक ध्रुवीकरण' के जाल में नहीं फंसना चाहते। वह जानते हैं कि बंगाल में ममता के पक्ष में खड़ा होना सीधे तौर पर भाजपा के हिंदुत्व के पिच पर खेलने जैसा होगा, जो उत्तर प्रदेश में उनके 'पीडीए' समीकरण को बिगाड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ की रैलियों में उमड़ता जनसैलाब और उनका आक्रामक तेवर यह साफ करता है कि भाजपा ने बंगाल को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। योगी का 'गौ-माता' और 'राम' का मुद्दा सीधे तौर पर बंगाल की सांस्कृतिक जड़ों को छूने का प्रयास है। वह ममता बनर्जी के उस 'गुस्से' को ढाल बना रहे हैं जो वह 'जय श्री राम' के नारों पर दिखाती रही हैं। योगी का यह कहना कि 'ममता दीदी राम नाम से चिढ़ती हैं', बंगाल के हिंदू मतदाताओं के मन में एक गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। वह इस लड़ाई को 'बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी' से मोड़कर 'हिंदुत्व बनाम तुष्टिकरण' पर ले आए हैं। कोलकाता के मेयर के बयान को आधार बनाकर उन्होंने बंगाली अस्मिता को बचाने का जो कार्ड खेला है, उसने टीएमसी की रणनीति को बैकफुट पर धकेल दिया है। बहरहाल, यह चुनाव केवल बंगाल की सत्ता का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। योगी आदित्यनाथ जहां अपनी 'हिंदुत्ववादी छवि' और 'कठोर प्रशासक' के ठप्पे को और मजबूत कर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव एक 'वेट एंड वॉच' की नीति पर चल रहे हैं। योगी के लिए बंगाल एक प्रयोगशाला है जहां वह अपने यूपी मॉडल की सफलता को परख रहे हैं, ताकि 2027 में वह और अधिक आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतर सकें। वहीं अखिलेश के लिए बंगाल एक ऐसी आग है जिससे वह अपने दामन को बचाकर निकलना चाहते हैं ताकि यूपी की जंग में वह बेदाग रहें। बंगाल के इस चुनावी रण में योगी की 'गर्जना' और अखिलेश का 'मौन' दोनों ही भारतीय राजनीति के भविष्य के गर्भ में छिपे बड़े बदलावों की पटकथा लिख रहे हैं। अब देखना यह है कि बंगाल की जनता योगी के 'रामराज्य' के आह्वान को चुनती है या ममता की 'अकेली लड़ाई' पर मुहर लगाती है।

(नोटः इस लेख में ये दिए गए विचार

किसानों को जमीन का 4 गुना मुआवजाः सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला, मनमाड-इंदौर रेल परियोजना को मिलेगी गति

सेंधवा (निर्मला वर्मा)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 22 अप्रैल को भोपाल स्थित सीएम हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस फैसले के तहत अब प्रदेश में किसी भी किसान की भूमि अधिग्रहण करने पर उसे गाइडलाइन वैल्यू का चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। इस घोषणा से किसानों को उनकी जमीन का वाजिब मूल्य मिलने के साथ ही विकास परियोजनाओं को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

मनमाड-इंदौर रेलवे संघर्ष समिति के प्रमुख मनोज मराठे ने इस निर्णय पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा भू-अर्जन मुआवजा फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 किया गया है, जिससे कुल मुआवजा राशि बढ़कर लगभग चार गुना तक हो जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि ग्रामीण क्षेत्र में जमीन का बाजार मूल्य 10 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है, फैक्टर 2 लागू होने पर यह 20 लाख हो जाता है, और परिसंपत्तियों (जैसे पेड़, कुआं) का मूल्य जोड़कर 22 लाख होता है। इसके बाद 100% सोलैटियम जोड़ने पर कुल मुआवजा 44 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। श्री मराठे ने बताया कि इस विषय को लेकर उन्होंने पूर्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष माननीय अंतर सिंह आर्य से भेंट कर किसानों को बाजार मूल्य के अनुरूप मुआवजा दिलाने की मांग रखी थी। उन्होंने बताया कि रेल परियोजनाओं सहित अन्य विकास कार्यों में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा कम मिलने से आदिवासी एवं सामान्य किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था, जिससे कई स्थानों पर परियोजनाओं में बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं। इस संबंध में 6 अप्रैल को दिल्ली में रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में भी मनमाड-इंदौर परियोजना को तीन चरणों में विभाजित कर अलग-अलग टेंडर जारी करने, उचित मुआवजा देने तथा सेंधवा से जुलवानिया के बीच रेलवे यार्ड स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आयोग अध्यक्ष श्री आर्य ने इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा। मराठे ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अब बाजार मूल्य के आधार पर बढ़ा हुआ मुआवजा देने की घोषणा सराहनीय और किसानों के हित में बड़ा कदम है। इससे न केवल किसानों को न्याय मिलेगा, बल्कि मनमाड-इंदौर रेल परियोजना सहित अन्य विकास कार्यों में भी अब अधिग्रहण संबंधी बाधाएं कम होंगी और परियोजनाएं तय समय पर पूर्ण हो सकेंगी। उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य का मनमाड-इंदौर रेलवे संघर्ष समिति की ओर से आभार व्यक्त किया।

मार्निंग ग्रुप द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस मनाया

सेंधवा (निर्मला वर्मा)। 22 अप्रैल 2026 को 56वां विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य विषय 'हमारी शक्ति, हमारा ग्रह' है। यह दिन 1970 से पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित है, जो 190+ देशों में प्लास्टिक को कम करने, पेड़ लगाने और रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर पूरे देश में पर्यावरण को शुद्ध व अनुकूल बनाने हेतु पूरे देश में मुहिम चल रही है कि पौधा रोपण कर पर्यावरण संरक्षण करे। लोगो में वृक्षारोपण को लेकर जागृति देखी जा रही है। इस संबंध में मार्निंग ग्रुप द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रुप के सदस्यों के जन्मदिन पर एक पौधे का रोपण किया जाता हैं।पौधा रोपण के बाद उसे पेड़ बनने तक की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ग्रुप के सदस्य अपने ऊपर लेकर समय पर पानी खाद व सुरक्षा के लिए टीगार्ड लगाकर उसकी सुरक्षा करते है। चार साल में तीन पौधे लगाए आज वे बड़े पेड़ बन गए। विश्व पृथ्वी दिवस पर मार्निंग ग्रुप के सदस्यों ने पेड़ के साथ सेल्फी भी ली। इस अवसर पर मार्निंग ग्रुप के सुनील अग्रवाल ने कहा कि वृक्षारोपण के नाम पर बड़े बड़े आयोजन कर सेल्फी लेकर फोटो अखबार, मीडिया व सोशल ग्रुप में शेयर किए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। किंतु पौधा रोपण करने व फोटो खींचने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। पौधे को बच्चे की तरह देख भाल कर उसे पालना होता है। एक साल तक पौधे को बड़ा होने तक उसका ध्यान व समय समय पर पानी खाद डालने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि लोग वृक्षारोपण पर बढ़ चढ़ कर भाग लेते है उसके बाद उस पौधे की सूद नहीं लेते। इसे वृक्षारोपण का कोई महत्व नहीं है। प्रकृति की वनदेवी भी इससे नाराज होती है। मार्निंग ग्रुप का पर्यावरण संरक्षण का सच्चा मंत्र है कि हम 50 पौधे नहीं लगाए हम सिर्फ एक, दो ही पौधा लगाए उसका पूरा ध्यान रख कर बड़ा करें। पौधे से पेड़ बनाए बच्चों की तरह परवरिश करें यह सबसे बड़ा पुण्य कार्य होता है। आपके मन को भी शांति मिलेगी। हम संकल्प ले कि हम दिखावा नही करेंगे। पौधे को पेड़ बनाए। इस दौरान मार्निंग ग्रुप के गिरधारी गोयल, प्रदीप नाईक, प्रभाकर पाटिल, अनिल सिंधाने मौजूद थे।

पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर बैंसरन घाटी में श्रद्धांजलि

सेंधवा के व्यापारी शैलेंद्र अग्रवाल ने किया नमन

सेंधवा (निर्मला वर्मा)। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित बैंसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए भीषण आतंकी हमले की पहली बरसी पर पूरे देश में शोक और श्रद्धांजलि का माहौल रहा। इस हृदयविदारक घटना में 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिनमें अधिकांश हिंदू पुरुष पर्यटक शामिल थे। आतंकियों ने निर्दोष लोगों से धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाकर और पहचान सुनिश्चित करने के बाद गोली मारकर हत्या की थी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।

इस दर्दनाक घटना की पहली वर्षगांठ पर सेंधवा के पप्लाइवुड व्यापारी शैलेंद्र अग्रवाल स्वयं पहलगाम पहुंचे और बैंसरन घाटी में बने स्मारक स्थल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उस स्थान को नमन किया, जहां आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों पर गोलियां बरसाकर कई परिवारों की खुशियां छीन ली थीं। उनकी स्मृतियों को याद रखने हेतु बेस्टन स्मारक बनाया गया । हमले में जान गवाने वाले 26 लोगों के नाम अंकित है । शैलेंद्र अग्रवाल ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह घटना न केवल मानवता पर हमला थी, बल्कि देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने का प्रयास भी था। उन्होंने कहा कि आतंकियों का उद्देश्य लोगों में भय पैदा कर कश्मीर से दूर रखना था, लेकिन देशवासियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और आज भी बड़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर पहुंचकर यह संदेश दे रहे हैं कि आतंक के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरा देश एक है। हम आतंकवाद के सामने कभी झुकने वाले नहीं हैं। निर्दोष लोगों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी।अग्रवाल ने सभी मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और देश की एकता एवं शांति बनाए रखने का संकल्प दोहराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 22 अप्रैल 2025 को हुए इस आतंकी हमले में एक नेपाली नागरिक, एक मुस्लिम टट्टू संचालक सहित 24 हिंदू पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। मृतकों में नेवी के लेफ्टीनेंट, बैंक मैनेजर, एयरफोर्स अधिकारी के परिजन और व्यापारी वर्ग के लोग भी शामिल थे। इस कायराना हमले के बाद पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ गहरा आक्रोश देखने को मिला था।

कांग्रेसियों ने संसद में कौरवों की तरह किया नारी का अपमान- सीएम डॉ. मोहन यादव

सागर ■

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को सागर जिले के नरयावली में सांदपनी स्कूल का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंच से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कांग्रेस की महाभारत के कौरवों से तुलना करते हुए कहा- जैसे कौरवों ने द्रोपदी का चीर हरण कर नारी अपमान किया, वैसा ही बीते दिनों कांग्रेसियों ने संसद में किया। पीएम मोदी द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल का विरोध करके कांग्रेसियों ने देश की महिलाओं का अपमान किया है। वहां कौरव थे और यहां कांग्रेसी है।

सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी की भावना थी, प्रेम और सबको साथ लेकर चलने के लिए हमारी बहनों को उनका अधिकार दिया जाए, लेकिन कौरवों की तरह इस कांग्रेस का मन नहीं था। तीन तलाक के मामले में भी राहुल गांधी के पिता ने बहनों के भत्तों का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठुकराया था। इसलिए बहनों गांठ बांधकर रखना, जिस दिन जरूरत पड़ी तो कांग्रेस से हिसाब जरूर लेना।

संगठन महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दे रहा

सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंच से आगे कहा कि हमारा संगठन महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दे रहा है। हमारी सरकार में 17 बहनें कलेक्टर हैं। सागर में सांसद, महापौर और कलेक्टर महिला है। लेकिन यह कांग्रेस को सुहाता नहीं है। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल हमारी सरकार महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिलाकर रहेगी, यह हमारा संकल्प है।

कड़ान सिंचाई परियोजना के पुनरीक्षण की घोषणा

सीएम ने नरयावली में 63.41 करोड़ रुपए के 75 निर्माण कार्यो का लोकार्पण व भूमिपूजन किया। यहां सीएम ने कड़ान सिंचाई परियोजना के पुनरीक्षण की घोषणा की, जिसमें 240 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 30 हजार हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। मकरोनिया चौराहे पर फ्लाई ओवर बनाने सहित पुल, सडक जैसे कार्यों की घोषणा की। सीएम ने कहा कि अरब देशों में युद्ध के कारण देश में बारदाने का संकट आ गया था। इधर किसानों ने गेहूं का दोगुना उत्पादन किया। ऐसे में हमारे पास चुनौती थी कि हम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए बारदाने की व्यवस्था कैसे करें, हमने बोरी की व्यवस्था की और खरीदी शुरू की। किसान चिंता न करें किसान का दाना-दाना सरकार खरीदेगी। केंद्र ने 78 लाख टन गेहूं खरीदने का कोटा दिया है, जिसे बढ़ाने की मांग हमने की है। सीएम ने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि अब किसानों की जमीन का अधिग्रहण होने पर उन्हें चार गुना मुआवजा दिया जाएगा।

एमपी में बनेगी 21 मीटर चौड़ी फोरलेन सड़क, खाटू श्याम मंदिर की राह होगी आसान

राजगढ़ ■

नेशनल हाईवे का संगम कहे जाने वाले ब्यावरा शहर को अब नई रफ्तार मिलने जा रही है। लगातार बढ़ते ट्रैफिक और हादसों के चलते अब आधुनिक ग्रेड सेपरेटेड फोरलेन बायपास बनने जा रहा है, जो न सिर्फ ट्रैफिक को व्यवस्थित करेगा बल्कि सुरक्षित सफर भी संभव बनाएंगा।

करीब 66 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले उक्त प्रोजेक्ट का काम भी शुरू हो चुका है। खास बात यह है कि इस बार पुराने अनुभवों से सीख लेकर डिजाइन तैयार किया गया है, ताकि हाईवे और लोकल ट्रैफिक पूरी तरह अलग रह सके। बायपास पर हाईवे का ट्रैफिक पूरी तरह सेपरेट रहेगा, यानी फोरलेन बायपास में एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी। वहीं लोकल के ट्रैफिक के लिए दोनों तरफ सर्विस रोड बनेगा। जिससे आए दिन होने वाले सड़क हादसों से राहत मिलेगी। उक्त प्रोजेक्ट को अक्टूबर-2025 में स्वीकृति मिली। जिसकी शुरूआत में लागत 96 करोड़ रुपए थी, लेकिन बाद में 66.37 करोड़ रुपए हो गई। प्रोजेक्ट का काम अब शुरू हो चुका है। दो हिस्सो में इसका काम होना है। जिसमें पहला हिस्सा खाटू श्याम मंदिर से गुना बायपास और दूसरा हिस्सा, राजगढ़ बायपास से भोपाल बायपास शामिल है। जिसकी कुल लंबाई करीब करीब 3.5 किमी है। डेढ़ साल में इसका काम पूरा करना है। यानी मार्च-2027 तक बायपास पूरी तरह तैयार हो जाए।

होटल में मिले गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के शव

रीवा ■

मध्यप्रदेश के रीवा में एक होटल के कमरे में गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रेमी जोड़ा एक ही गांव का रहने वाला था और उनके बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग होने की बात सामने आई है। शुरूआती जांच में पता चला है कि युवती घर से शॉपिंग का कहकर निकली थी और प्रेमी के साथ होटल पहुंची थी। पुलिस को होटल के कमरे से जहर, बीयर और शराब की बोतल भी मिली है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

रीवा के समान थाने के रिंग रोड स्थित द एम्पायर होटल के कमरा नंबर 110 में युवक और युवती के शव मिले हैं। दोनों एक दिन पहले घर से निकले थे। मृतकों की पहचान रवि साकेत (25) और काजल साकेत (22) के तौर पर हुई है जो कि रामपुर बघेलान थाने के बेला गांव के रहने वाले थे। युवती के परिजन ने बताया कि काजल घर से शॉपिंग करने का कहकर निकली थी। जब काजल काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिजन ने उसकी तलाश की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। होटल के स्टाफ से पता चला है कि दोनों बुधवार को करीब 11:30 बजे होटल में आए थे और उसके बाद होटल के कमरे में ही थे। गुरुवार की सुबह कर्मचारियों ने होटल का कमरा खुलवाने का प्रयास किया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। संदेह होने पर उन्होंने दोपहर साढ़े बारह बजे पुलिस को सूचना दी जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची तो घटनास्थल का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था।

सायरन बजाते दौड़ रही एंबुलेंस में इश्कबाजी! कॉलेज की लड़की के साथ पकड़ाया ड्राइवर

छतरपुर ■

अभी तक 108 एंबुलेंस के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं लेकिन मध्यप्रदेश के छतरपुर में एंबुलेंस के दुरुपयोग का जो मामला सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। यहां एक एंबुलेंस में इश्कबाजी करते हुए ड्राइवर को पकड़ा गया है। एंबुलेंस में कॉलेज छात्रा को बैठाकर ड्राइवर सायरन बजाते हुए रोड पर तेज रफ्तार में एंबुलेंस को दौड़ा रहा था। जब लोगों ने एंबुलेंस में लड़की को बैठे देखा तो उन्होंने एंबुलेंस का पीछा कर रुकवाया तो एंबुलेंस में हो रही इश्कबाजी का खुलासा हुआ।

छतरपुर जिले में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा 108 एम्बुलेंस के दुरुपयोग का एक गंभीर मामला सामने आया है। जिस एम्बुलेंस का उपयोग मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए किया जाना चाहिए, उसमें एक वाहन चालक छात्रा को बैठाकर ले जाते हुए पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार, एक स्थानीय व्यक्ति ने सड़क पर 108 एम्बुलेंस को सायरन बजाते हुए तेज रफ्तार में जाते देखा। आमतौर पर सायरन का मतलब किसी मरीज की गंभीर स्थिति होती है, लेकिन जब व्यक्ति की नजर अंदर पड़ी तो नजारा कुछ और ही था। एम्बुलेंस के अंदर मरीज की जगह एक युवती (छात्रा) बैठी हुई थी। मामला संदिग्ध लगने पर युवक ने अपनी बाइक से एम्बुलेंस का पीछा किया और कुछ दूरी पर उसे रुकवा लिया।

अनियंत्रित गेमिंग के दौर के बाद नियंत्रण का कड़ा अध्याय

रात की खामोशी अब विश्राम नहीं, बल्कि स्क्रीन की चमक में डूबकर एक नई सोच को जन्म दे रही है, जो अनजाने में पूरी पीढ़ी का मन गढ़ रही है। उंगलियों की निरंतर हलचल ने सोच की गहराई को कमजोर कर दिया है, और आभासी उपलब्धियों का आकर्षण वास्तविक जीवन की प्राथमिकताओं को पीछे धकेल रहा है। ऐसे नाजुक मोड़ पर 1 मई 2026 से लागू होने जा रहा ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ओजीएआई) केवल प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि डिजिटल अनुशासन को फिर से स्थापित करने का प्रभावी प्रयास है। यह पहल उस अनियंत्रित डिजिटल बहाव को थामने की शुरूआत है, जिसने युवाओं को लत, असंतुलन और मानसिक दबाव के जाल में फँसा दिया है।

प्रो. आरके जैन
लेखक

दैनिक ग्लोबल हेराल्ड

डिजिटल जगत को संतुलित दिशा देने के उद्देश्य से प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025 (प्रोगा) के तहत गठित ओजीएआई भारत के शासन में एक अहम बदलाव का संकेत है। यह स्वायत्त संस्था ऑनलाइन गेमिंग को तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत करेगी और रियल मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगी। सुरक्षित सोशल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन को अधिकांश मामलों में स्वैच्छिक रखा गया है। ओजीएआई को सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिसमें गेम्स की राष्ट्रीय रजिस्ट्री तैयार करना, अनुपालन की निगरानी और अवैध गेम्स को ब्लैकलिस्ट करना शामिल है। वहीं, सुरक्षित और शैक्षिक खेलों को राष्ट्रीय रजिस्ट्री में शामिल कर उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि गेमिंग केवल लत नहीं, बल्कि सीख और विकास का साधन बन सके। स्क्रीन की चकाचौंध अब युवाओं को इस तरह बाँध रही है कि वास्तविक जीवन का संतुलन बिगड़ने लगा है। आज की युवा पीढ़ी जिस तरह ऑनलाइन गेमिंग के प्रभाव में फँसती जा रही है, वह महज सामाजिक चुनौती नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में चेतावनी दी गई है कि 15 से 29 वर्ष के युवाओं में अत्यधिक स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन गेमिंग से चिंता, अवसाद, अनिद्रा और ध्यान की कमी तेजी से बढ़ रही है। रियल मनी गेम्स से होने वाला आर्थिक नुकसान परिवारों की स्थिरता को भी डगमगा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण यह भी सुझाव देता है कि डिजिटल एडिक्शन से निपटने के लिए टेली-मानस जैसे मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को और मजबूत किया जाए। ओजीएआई का हस्तक्षेप इस बिगड़ती परिस्थिति को संभालने की दिशा में एक ठोस और समयानुकूल पहल है। नियमन की कसौटी पर खरा उतरने वाला ढांचा तभी सार्थक होता है, जब उसमें अधिकार के साथ जवाबदेही भी स्पष्ट हो—और ओजीएआई इसी संतुलन का सशक्त उदाहरण बनकर उभरता है। इसे सिविल कोर्ट के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे यह गेम्स के वर्गीकरण, पंजीकरण और अनुपालन की निगरानी प्रभावी ढंग से कर सके। केंद्रीय शिकायत निवारण तंत्र उपयोगकताओं को त्वरित न्याय उपलब्ध कराएगा, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से संभव होगा। साथ ही, पेमेंट गेटवे, ऐप स्टोर्स और अन्य डिजिटल मध्यस्थों को भी जवाबदेह बनाकर एक व्यापक और सुरक्षित गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जाएगा, जो उपयोगकर्ता हितों की रक्षा सुनिश्चित करेगा। डिजिटल अनुशासन और जिम्मेदार व्यवहार की स्पष्ट दिशा तय करते हुए ओजीएआई का आगमन परिपक्व और दूरदर्शी सोच का संकेत देता है। अब गेमिंग केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहेगा, बल्कि जिम्मेदारी, संतुलन और सजगता का विषय बनेगा। एडिक्टिव डिजाइन, लूट बॉक्सेस और भ्रामक विज्ञापनों पर कड़े नियंत्रण से उपयोगकताओं को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय वातावरण मिलेगा। ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलने से युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने और सशक्त करियर बनाने के अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि सरकार इसे प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता देकर प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम चला रही है। साथ ही, शैक्षिक गेम्स शिक्षा को रोचक, प्रभावी और सहभागितापूर्ण बनाकर डिजिटल दुनिया के सकारात्मक पक्ष को और अधिक स्पष्ट रूप से सामने लाएंगे। परिवर्तन की इस व्यापक रूपरेखा के साथ चुनौतियों की परतें भी समान रूप से मौजूद हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विदेशी सर्वरों से संचालित अवैध प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण स्थापित करना तकनीकी दृष्टि से जटिल कार्य है, जिसमें ओजीएआई आईटी एक्ट के तहत ब्लॉकिंग की सिफारिश कर सकता है। इसके साथ ही, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रभावी समन्वय बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण पहलू रहेगा। छोटे डेवलपर्स के लिए अनुपालन सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है, जिससे नवाचार प्रभावित होने की आशंका है। इसलिए ओजीएआई को लचीली और डेटा-आधारित नीतियां अपनानी होंगी, ताकि नियमन और रचनात्मकता के बीच संतुलन बना रह सके। इस परिवर्तन की वास्तविक सफलता केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समाज की सक्रिय और जागरूक भागीदारी पर भी समान रूप से निर्भर करेगी। माता-पिता को बच्चों के स्क्रीन टाइम पर सतर्क और संतुलित नियंत्रण रखना होगा, स्कूलों को जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सही दिशा और समझ विकसित करनी होगी, तथा मीडिया को भी इस विषय को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करना होगा। जब समाज इस पहल को सकारात्मक रूप से अपनाएगा, तभी इसका व्यापक और प्रभावी परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ओजीएआई वास्तव में एक सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है, जिसकी सफलता हर नागरिक की सहभागिता से ही सुनिश्चित हो सकती है। जब भविष्य की दिशा तय होती है, तो कुछ तिथियाँ इतिहास में मील का पत्थर बन जाती हैं—1 मई 2026 भी ऐसा ही एक निर्णायक क्षण साबित होगा। ओजीएआई का प्रभावी क्रियान्वयन न केवल युवाओं को लत के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखेगा, बल्कि एक संतुलित, सुरक्षित और जिम्मेदार गेमिंग संस्कृति को भी सुदृढ़ करेगा। यदि यह पहल दूरदर्शिता और सतत प्रयासों के साथ आगे बढ़ती है, तो भारत वैश्विक परिदृश्य पर एक अनुकरणीय मॉडल बन सकता है। यह केवल एक नीति नहीं, बल्कि एक सशक्त संकल्प है—जो डिजिटल भारत को अधिक जिम्मेदार, सुरक्षित और जागरूक राष्ट्र में रूपांतरित करने की क्षमता रखता है।

(नोटः इस लेख में ये दिए गए विचार लेखक के अपने विचार हैं)

सम्पादकीय

चुनाव आयोग की तार्किक विसंगति बनाम अतार्तिक विसंगति?

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में तार्किक विसंगति के नाम पर 27 लाख, 10 हजार नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए हैं। इन नागरिक मतदाताओं को अंतिम समय तक वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 19 न्यायाधिकरण भी बनाए गए। यह भी मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाए। लाखों की संख्या में मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो गए। यह सब लोकतांत्रिक, संवैधानिक संस्थाओं ने अधिकारों के नाम पर किया है। इस प्रक्रिया में इन लाखों मतदाताओं के अधिकार कहां चले गए। इसमें कौन सा तर्क है, और कौन सा वितर्क है? इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। जो ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट आदेश पर बनाए गए थे, उन्हें मतदान के दो दिन पहले तक सुनवाई कर निर्णय देना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दो दिन पहले तक मतदाता सूची को अपडेट करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी थी। याचिकाकताओं को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिलाया गया था, मतदाताओं के साथ न्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, ट्रिब्यूनल सब जगह मतदाता घूमते रह गए। कहीं से भी न्याय नहीं मिला। लाखों मतदाताओं ने सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन लगाए। 21 अप्रैल तक मात्र 138 लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए। चुनाव आयोग ने तार्किक विसंगति के पक्ष में जो तर्क सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में दिए थे, वह सब हवा-हवाई साबित हुए। 2002 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम थे, तार्किक विसंगति के नाम पर उनके भी नाम काट दिए गए। इसका क्या तर्क है, यह चुनाव आयोग नहीं बता पा रहा है। इसको देखते हुए यही कहा जा सकता है- समरथ को नहीं दोष गुसाईं। चुनाव आयोग ने तार्किक विसंगति के नाम पर पहले 60 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काट दिए। जिनके नाम कटे उसमें सारे गरीब- गुरवे थे, जो कई दिनों तक नाम जुड़वाने के लिए अपनी नौकरी, कारोबार, मजदूरी छोड़कर चक्कर लगाते रह गए। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के नाम पर उन्हें भूखा भी रहना पड़ा। मजदूरी पर नहीं जाने के कारण उनके परिवार के लोगों को खाने-पीने और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। जिस जनता के अधिकारों के लिए चुनाव आयोग, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, वह उनके अधिकारों की रक्षा करने में सफल नहीं हो पाए। तार्किक विसंगति के नाम पर सही मतदाता सूची को बनाने के नाम पर लाखों मतदाताओं के नाम जोड़ने की जगह काटे गए है। करोड़ों रुपए इसमें सरकारी खजाने से खर्च किए गए। कई राज्यों के न्यायिक अधिकारियों को चुनाव के काम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगा दिया गया। इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। गरीब आखिर गरीब ही होता है। गलती कोई भी करे, गरीब के नसीब में यदि कष्ट लिखा हुआ है, तो कोई क्या कर सकता है। चुनाव आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तार्किक विसंगति की जो रूपरेखा तय की थी, उसका उपयोग केवल पश्चिम बंगाल में किया गया है। चुनाव आयोग और उसमें काम करने वाले लोगों ने डाटा एंट्री मे जो गलती की हैं, उनके द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर की गलतियों का खामियाजा पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को भोगना पड़ा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी आशंका की बात यह है, बांग्लादेश में जब शेख हसीना का चुनाव हुआ था। वहां पर भी कुछ इसी तरह की स्थितियां बनी थीं। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने शेख हसीना की पार्टी को चुनाव जिताने के लिए जो मदद की थी, अब वही सब कुछ पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में जिस तरह की क्रिया और प्रतिक्रिया की जा रही है। उसके परिणाम किस रूप में सामने आयेंगे कहना मुश्किल है। बांग्लादेश में भी बंगाली समुदाय और बंगाली संस्कृति के नागरिक थे। पश्चिम बंगाल में भी बंगाली हैं। बंगालियों का डीएनए एक तरह का है। यह आसानी से अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं।

सनत जैन
लेखक
ग्लोबल हेराल्ड

डिजिटल यादें और भूलने का अधिकार...

डॉ. सत्यवान सौरभ | लेखक

ग्लोबल हेराल्ड

भूल जाने का अधिकार (राइट टू बी फॉरगॉटन–आरटीबीएफ) आज के डिजिटल युग की सबसे जटिल और बहुआयामी कानूनी-नैतिक बहसों में से एक बन चुका है। इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकी के विस्तार ने सूचना को स्थायी, सर्वसुलभ और वैश्विक बना दिया है, जिसके कारण एक बार प्रकाशित हुई जानकारी लंबे समय तक ऑनलाइन बनी रहती है और व्यक्ति के जीवन को निरंतर प्रभावित करती है। ऐसे परिदृश्य में आरटीबीएफ व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी पुरानी, अप्रासंगिक, भ्रामक या हानिकारक जानकारी को हटाने या कम-से-कम उसकी दृश्यता को सीमित करने की मांग कर सके। यह अधिकार विशेष रूप से उन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ किसी व्यक्ति के अतीत की जानकारी उसके वर्तमान जीवन, रोजगार, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हो। पहली दृष्टि में यह अधिकार मानवीय गरिमा, निजता और आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है, लेकिन जब यह प्रेस की स्वतंत्रता और जनता के जानने के अधिकार से टकराता है, तब यह एक गंभीर संवैधानिक और नैतिक द्वंद्व उत्पन्न करता है, जिसका समाधान सरल नहीं है। आरटीबीएफ की अवधारणा का वैश्विक उद्भव 2014 में यूरोपीय संघ के प्रसिद्ध गूगल स्पेन मामले से हुआ, जहाँ न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सर्च इंजन कुछ परिस्थितियों में ऐसी जानकारी को अपने सर्च परिणामों से हटा सकते हैं,...

जो अब अप्रासंगिक हो चुकी हो या व्यक्ति की निजता का अनावश्यक उल्लंघन करती हो। इस निर्णय ने डिजिटल अधिकारों के क्षेत्र में एक नया अध्याय खोला और इसके परिणामस्वरूप जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) के अनुच्छेद 17 में मिटाने का अधिकार (राइट टू इरेजर) को कानूनी मान्यता दी गई। हालांकि, यूरोपीय मॉडल ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जनहित, ऐतिहासिक अभिलेखों और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण अपवादों के साथ संतुलित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, आरटीबीएफ को एक सशर्त अधिकार के रूप में विकसित किया गया, जो व्यक्ति की निजता और समाज के व्यापक हित के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। भारत में आरटीबीएफ का कोई स्पष्ट और समर्पित वैधानिक ढाँचा अभी तक विकसित नहीं हुआ है, लेकिन इसका आधार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित गोपनीयता के अधिकार में देखा जा सकता है, जिसे 2017 के ऐतिहासिक पुट्टास्वामी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। इसके अतिरिक्त, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी एक्ट) सीमित रूप से डेटा मिटाने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन यह मीडिया रिपोर्टों, सार्वजनिक अभिलेखों और पत्रकारिता से जुड़े मामलों में स्पष्ट दिशानिर्देश देने में अभी अपर्याप्त साबित होता है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 भी शिकायत निवारण का एक ढाँचा प्रदान करते हैं, परंतु वे इस जटिल संतुलन को प्रभावी ढंग से संभालने में सक्षम नहीं हैं। परिणामस्वरूप, भारत में आरटीबीएफ के अनुप्रयोग को लेकर न्यायिक निर्णयों में असंगति और अस्पष्टता देखी जा रही है, जो एक सुसंगत नीति की आवश्यकता को रेखांकित करती है। आरटीबीएफ और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच टकराव को समझने के लिए सूचनात्मक आत्म-निर्धारण की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत डेटा, डिजिटल पहचान और ऑनलाइन उपस्थिति पर नियंत्रण का अधिकार देता है। आज के समय में, जब किसी व्यक्ति की ऑनलाइन छवि उसके पेशेवर अवसरों, सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, तब यह अधिकार और भी प्रासंगिक हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी समय आपराधिक आरोप लगे हों, लेकिन बाद में वह अदालत द्वारा बरी कर दिया गया हो, तब भी इंटरनेट पर उपलब्ध पुरानी समाचार रिपोर्टें उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। ऐसे मामलों में आरटीबीएफ व्यक्ति को एक दूसरा मौका प्रदान करने का माध्यम बन सकता है, जिससे वह अपने अतीत की छाया से मुक्त होकर वर्तमान में आगे बढ़ सके। दूसरी ओर, प्रेस की स्वतंत्रता, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) में निहित है, लोकतंत्र का एक मूलभूत स्तंभ है। यह केवल अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं, बल्कि जनता के जानने के अधिकार का भी प्रतीक है। मीडिया की भूमिका केवल सूचना देना नहीं, बल्कि सत्ता की निगरानी करना, भ्रष्टाचार को उजागर करना और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी है। यदि आरटीबीएफ का उपयोग व्यापक रूप से समाचार रिपोर्टों, खोजी पत्रकारिता या सार्वजनिक हित से जुड़ी जानकारी को हटाने के लिए किया जाने लगे, तो यह लोकतांत्रिक जवाबदेही को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है। विशेष रूप से तब, जब प्रभावशाली व्यक्ति या सार्वजनिक पदाधिकारी अपने अतीत से जुड़ी असुविधाजनक जानकारी को हटाने के लिए इस अधिकार का उपयोग करें, तब यह समाज के लिए खतरनाक प्रवृत्ति बन सकती है। हाल के वर्षों में कुछ न्यायिक मामलों में आरटीबीएफ के नाम पर गैग ऑर्डर जारी किए गए हैं, जो मीडिया को किसी विशेष जानकारी के प्रकाशन या प्रसार से रोकते हैं। ये आदेश कई बार प्रायर रेस्ट्रेंट का रूप ले लेते हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्व-प्रतिबंध होता है और संवैधानिक दृष्टि से अत्यंत संदेहास्पद माना जाता है। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब ऐसे आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किए जाते हैं, बिना मीडिया या अन्य संबंधित पक्षों को सुने। इससे न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिह्न लगते हैं। यद्यपि कुछ मामलों में अदालतों ने बरी हुए व्यक्तियों के पक्ष में निर्णय देते हुए पुरानी जानकारी को हटाने का आदेश दिया है, वहीं अन्य मामलों में प्रेस की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हुए ऐसे आदेशों को निरस्त भी किया गया है। इन विरोधाभासी निर्णयों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में इस विषय पर एक सुसंगत और स्पष्ट कानूनी ढाँचे की तत्काल आवश्यकता है। आरटीबीएफ के संभावित दुरुपयोग के खतरे भी कम नहीं हैं। प्रभावशाली व्यक्ति, राजनेता या आर्थिक अपराधों में संलिप्त लोग इस अधिकार का उपयोग अपने अतीत को साफ करने और सार्वजनिक स्मृति को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं।

इसके अलावा, स्ट्रैटेजिक लॉसूट्स अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन (एसएलएपीपी) जैसे मुकदमे पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर कानूनी दबाव डालने का एक साधन बन सकते हैं, जिससे वे संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने से बचें। साथ ही, स्ट्राइसैंड इफेक्ट का खतरा भी बना रहता है, जहाँ किसी जानकारी को दबाने का प्रयास उसे और अधिक प्रचारित कर देता है, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती है। इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि भारत एक सुविचारित वैधानिक संतुलन परीक्षण विकसित करे, जो आरटीबीएफ और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच उचित संतुलन स्थापित कर सके। इस परीक्षण में कुछ प्रमुख तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए, जैसे कि जानकारी की प्रकृति–क्या वह पूरी तरह निजी है या उसका स्पष्ट संबंध जनहित से है; संबंधित व्यक्ति की भूमिका–क्या वह एक निजी नागरिक है या सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ व्यक्ति; मामले की स्थिति–क्या यह केवल आरोप का चरण है या अंतिम निर्णय आ चुका है; और वास्तविक हानि का आकलन–क्या सूचना की उपलब्धता से व्यक्ति को ठोस और सिद्ध नुकसान हो रहा है या नहीं। इसके अतिरिक्त, कम से कम प्रतिबंधक विकल्प के सिद्धांत को भी अपनाया जाना चाहिए, जिसके तहत किसी जानकारी को पूरी तरह हटाने के बजाय पहले यह देखा जाए कि क्या उसे संशोधित किया जा सकता है, उसमें संदर्भ जोड़ा जा सकता है या केवल सर्च परिणामों से हटाया जा सकता है।

(नोटः इस लेख में ये दिए गए विचार लेखक के अपने विचार हैं)

बढ़ती गर्मी से एक दशक में खेत उत्पादन 30 प्रतिशत घट सकता है

क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो स्थिति बनी है, उससे पूरा विश्व परेशान है। यह ऐसी समस्या है, जो किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है, क्योंकि पृथ्वी को जो नुकसान हुआ है, उसका परिणाम अब भुगतना पड़ रहा है। इसके कारण दुनिया भर में कभी भी बारिश, गर्मी, ठंड, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खाद्य संकट और मौसम व वातावरण में बदलाव जैसी समस्याएं तथा बीमारियों में वृद्धि जैसी चिंताएं बढ़ गई हैं। यदि भारत की बात करें, तो यहां खेती पर व्यापक असर पड़ा है। भारत में लगभग 60 प्रतिशत लोग खेती पर ही निर्भर हैं।

ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा असर खेती पर पड़ा है और आने वाले समय में स्थिति और खराब होने की आशंका है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि फसलों की गुणवत्ता पर भी व्यापक असर पड़ रहा है। इस बदलाव के कारण देश में खेती के सामने बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ है और इसके चलते खाद्य सुरक्षा पर भी गंभीर संकट खड़ा हो गया है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र और उससे जुड़े अन्य संगठनों तथा खाद्य और कृषि संगठनों द्वारा चेतावनी दी गई है कि लगातार बढ़ती गर्मी, सूखा, बाढ़ और जमीन की पोषक क्षमता में कमी दुनिया भर को नुकसान पहुंचा रही है। खासकर मध्य-पूर्व के देशों को इसका अधिक नुकसान हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2040 तक यदि तापमान में औसतन 1.5 डिग्री की वृद्धि होती है, तो खेती और उसकी गुणवत्ता पर व्यापक नकारात्मक असर पड़ेगा। बढ़ते कार्बन उत्सर्जन के कारण इस सदी में दुनिया भर में भुखमरी, बाढ़, सूखा और पलायन जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। यदि गर्मी इसी तरह बढ़ती रही, तो एशिया के देशों में कृषि उत्पादन में 30 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि विकास की अंधी दौड़ में हम यह भूल रहे हैं कि आज भी दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं, जिन्हें रोजाना भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें दो वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में 2030 तक दुनिया से भुखमरी खत्म करने का वैश्विक लक्ष्य हासिल होना मुश्किल नजर आता है। दूसरी ओर देश में औसत वर्षा में भी बड़ा अंतर आया है। उन्नीसवीं सदी की तुलना में बीसवीं सदी में वर्षा कम हुई है। इसके अलावा गंगोत्री हिमनदी भी हर साल घट रही है और अन्य नदियों के जलस्तर में भी कमी आ रही है। पानी की कमी के कारण खेती में भी कठिनाई बढ़ रही है। चिंताजनक बात यह है कि एक तरफ क्लाइमेट चेंज का असर उत्पादन पर पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर फसल की गुणवत्ता में गिरावट, अनाज की बढ़ती कीमतें और किसानों की आय में कमी भी स्थिति को प्रभावित कर रही है। उत्पादन बढ़ाने में उपजाऊ भूमि, पानी, अनुकूल मौसम, रोग और कीटों से सुरक्षा जैसी बातें भी महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें से कोई एक भी घटक कमजोर पड़ता है, तो उत्पादन प्रभावित होता ही है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण पिछले एक दशक में तापमान बढ़ा है और कई अन्य समस्याएं भी पैदा हुई हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं, जिन्हें विशेष तापमान और वातावरण की आवश्यकता होती है। जैसे ही तापमान बढ़ता है या मौसम बदलता है, उन पर नकारात्मक प्रभाव शुरू हो जाता है। गेहूं, सरसों, जौ और आलू के लिए कम तापमान जरूरी होता है। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, इनकी उपज प्रभावित होती है। इसी तरह अधिक गर्मी से मक्का, ज्वार और अन्य अनाज भी प्रभावित होते हैं। अधिक तापमान के कारण इन फसलों में दाने ठीक से नहीं बनते और गुणवत्ता घट जाती है, जिससे नुकसान होता है। खास बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग खाद्य सुरक्षा के चारों पहलुओं, भोजन की उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता को प्रभावित करता है। यदि तापमान लगातार बढ़ता रहा, तो भोजन की कमी और उससे जुड़े जोखिम बढ़ जाएंगे। वर्तमान रुझानों के अनुसार इस सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान 3.7 से 4.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर खेती पर पड़ेगा। गेहूं, ज्वार, सरसों और आलू जैसी फसलों की खेती कठिन हो जाएगी और कई बार असफल भी हो सकती है। दूसरी ओर यदि मक्का और अन्य अनाज में दाने नहीं बनेंगे और गुणवत्ता घटेगी तो उनकी खेती भी घाटे का सौदा बन जाएगी। किसानों को फसल लेने के बावजूद नुकसान उठाना पड़ेगा। तापमान बढ़ने से वर्षा में भी कमी आएगी, जिससे जमीन की नमी घटेगी और सूखे की स्थिति बढ़ेगी। बढ़ती गर्मी के कारण मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा भी कम होगी, जिससे उत्पादन क्षमता घटेगी। इसे पूरा करने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ेगा, जिससे जमीन की उर्वरता और कम होती जाएगी। आज दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। भारत भी उन शीर्ष 20 देशों में शामिल है, जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पिछले चार दशकों में पृथ्वी का तापमान 0.5 डिग्री बढ़ चुका है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हुई है। भारत में अधिकांश किसानों के पास छोटी जमीन है, जिससे उनकी आय और उत्पादन पर असर पड़ रहा है और उनकी स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि यहां की 60 प्रतिशत आबादी सीधे या परोक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। ऐसे में यदि खेती पर संकट बढ़ता है, तो लोगों की आय और खाद्य आवश्यकताओं पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा और खाद्य सुरक्षा के सामने बड़ा खतरा खड़ा होगा।

स्नेहा सिंह
लेखक
ग्लोबल हेराल्ड

(नोटः इस लेख में ये दिए गए विचार लेखक के अपने विचार हैं)

कर्म का फल हैं योनियां

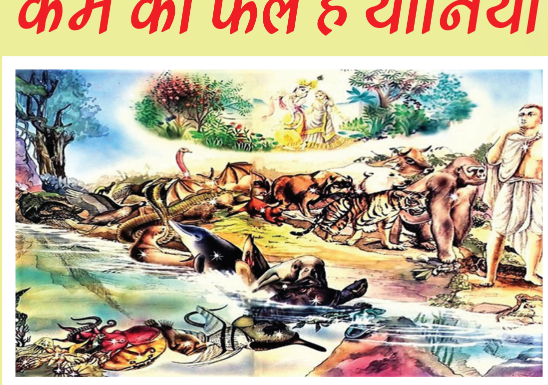

जीवों में शरीर तथा इन्द्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हैं। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न-भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृतिजन्य हैं। जीव के विभिन्न इन्द्रिय-सुखों से ये योनिया मिलती हैं जो इस या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख-दुख शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई सन्देह नहीं रहता, अतः वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैपुंठ लोक शुद्ध है, किन्तु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर-सुखों को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहता है।

यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इन्द्रियों का कार्य है। इन्द्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन हैं। यह शरीर तथा हेतु रूप इन्द्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं और जीव को पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख-दुख का कारण होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त होने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है। शरीर, पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं होती कि वह उस नियम को बदल सके। उदाहरण के लिए ज्यों ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है। यदि जीव को शूकर का शरीर प्राप्त होता है, तो वह मल खाने तथा शूकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त होता है, तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ विद्यमान रहता है।

ग्लोबल हेराल्ड में प्रकाशित होने वाले लेख लेखकों के निजी विचार है

व्यापार

शेयर बाजार गिरावट पर बंद, सेंसेक्स 852 , निफ्टी 205 अंक नीचे आया

मुंबई ■

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट पर बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट अमेरिक और ईरान के बीच तनाव को देखते हुए दुनिया कर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी नाकाबंदी से भी कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया जिससे भी बाजार पर दबाव पड़ा है।

आज कारोबार के दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 852.49 अंक फिसलकर 77,664 पर जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 205.05 अंक नीचे आकर 24,173.05 पर पहुंच गया।आज सेंसेक्स 77,574.18 के सबसे निचले स्तर पर वहीं निफ्टी 243 अंक

गिरकर 24,134.80 के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। इस प्रकार केवल दो सत्रों में सेंसेक्स करीब 1,600 अंक तक गिर गया है। आज सत्र के दौरान, व्यापक बाजार सूचकांक गिरे हैं। वहीं पिछले सत्र में बाजार में गिरावट के बावजूद व्यापक सूचकांक लाभ पर बंद हुए थे। निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में जहां 0.67 फीसदी की गिरावट रही। वहीं निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.41 फीसदी की गिरावट आई। क्षेत्रवार देखें तो निफ्टी फार्मा और निफ्टी मीडिया को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी ऑटो में 2.35 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 2.19 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.83 फीसदी, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.38 फीसदी रही।आज निफ्टी के सिप्ला, अदाणी इंटरप्राइजेज, कोल इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, अदाणी पोर्ट्स, ओनजीसी के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। दूसरी ओर , श्रीराम फाइनेंस, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, इंफोसिस, एसबीआई लाइफ, टीएमपीवी के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही।होर्मुज जलडमरूमध्य की जारी नाकाबंदी के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से भी निवेशकों ने बाजार से दूरी बनाये रखी। वहीं इससे पहले आज सुबह सेंसेक्स 604.76 अंक की गिरावट के साथ 77,911.73 पर खुला।

सोने की चमक पड़ी फीकी और चांदी भी हुई नरम

नई दिल्ली ■

देश में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। गुरुवार 23 अप्रैल को लगातार दूसरे दिन पीली धातु सस्ती हुई, जिससे निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए कुछ राहत मिली है।

राजधानी दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव 10 रुपये प्रति 10 ग्राम घटकर 1,41,990 रुपये पर आ गया है, जबकि मुंबई में यह 1,41,840 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इस गिरावट के पीछे वैश्विक तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार का दबाव प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। वहीं प्रतिभागियों के अपने दांव घटाने से चांदी की वायदा कीमत गुरुवार को 4,205 रुपये टूटकर 2,44,159 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर मई में आपूर्ति वाले

चांदी के अनुबंध का भाव 4,205 रुपये की गिरावट के साथ 2,44,159 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। इसमें 1,281 लॉट का कारोबार हुआ। विश्लेषकों ने बताया कि प्रतिभागियों की बिकवाली से मुख्य रूप से चांदी की कीमतों पर दबाव पड़ा। गुरुवार को 22 कैरेट सोना ही नहीं, बल्कि 24 कैरेट और 18 कैरेट वाले सोने की कीमतों में भी 10-10 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि एक दिन पहले 22 अप्रैल को दिल्ली के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 300 रुपये टूटकर करीब 1,57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 की लोकप्रियता आज भी बरकरार

नई दिल्ली ■

बाजार में अब रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 बाइक बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। यह अब केवल एक संग्रहणीय वस्तु के रूप में मौजूद है। अगर आप आज इस प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल के मालिक बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको इसके विशेष लघु मॉडल से संतोष करना होगा, जिसकी कीमत लगभग 88 हजार रुपये रखी गई है।

रॉयल एनफील्ड की यह मोटरसाइकिल सिर्फ एक वाहन नहीं थी, बल्कि इसने कंपनी की नई पहचान गढ़ने में अहम भूमिका निभाई थी। वर्ष 2009 में पेश की गई इस बाइक ने अपने पारंपरिक डिजाइन, दमदार इंजन और खास ध्वनि के कारण लोगों के दिलों में जगह बनाई।

लंबे समय तक यह उन लोगों की पहली पसंद रही, जो केवल गति नहीं बल्कि एक अलग और क्लासिक अनुभव की तलाश में रहते थे। हालांकि, इस लोकप्रिय मोटरसाइकिल का सफर वर्ष 2020 में समाप्त हो गया, जब कड़े उत्सर्जन मानकों के लागू होने के कारण कंपनी को इसे बंद करना पड़ा। इसके साथ ही इसका विशिष्ट इंजन और पहचान बन चुकी आवाज भी इतिहास का हिस्सा बन गई। वर्ष 2026 तक आते-आते रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 केवल एक संग्रहणीय वस्तु के रूप में रह गई है। कंपनी के परिधान और सहायक उत्पाद विभाग ने इसका एक विशेष लघु मॉडल पेश किया है, जो मूल मोटरसाइकिल की हूबहू झलक देता है। यह लघु मॉडल कोई सामान्य खिलौना नहीं है, बल्कि इसे बेहद सटीकता और बारीकी के साथ तैयार किया गया है। इसमें सैकड़ों छोटे पुर्जों का उपयोग किया गया है और इसका वजन भी उल्लेखनीय है, जिससे यह वास्तविक मोटरसाइकिल जैसा अनुभव देता है। इसे कई आकर्षक रंगों में पेश किया गया है, जो कभी इस मोटरसाइकिल की पहचान रहे थे। इस खास मॉडल की बुकिंग सीमित समय के लिए खुली है और इसे कंपनी के आधिकारिक माध्यमों से खरीदा जा सकता है। बुकिंग के लिए एक निश्चित अग्रिम राशि जमा करनी होती है, जिसके बाद यह विशेष मॉडल आपके संग्रह का हिस्सा बन सकता है।

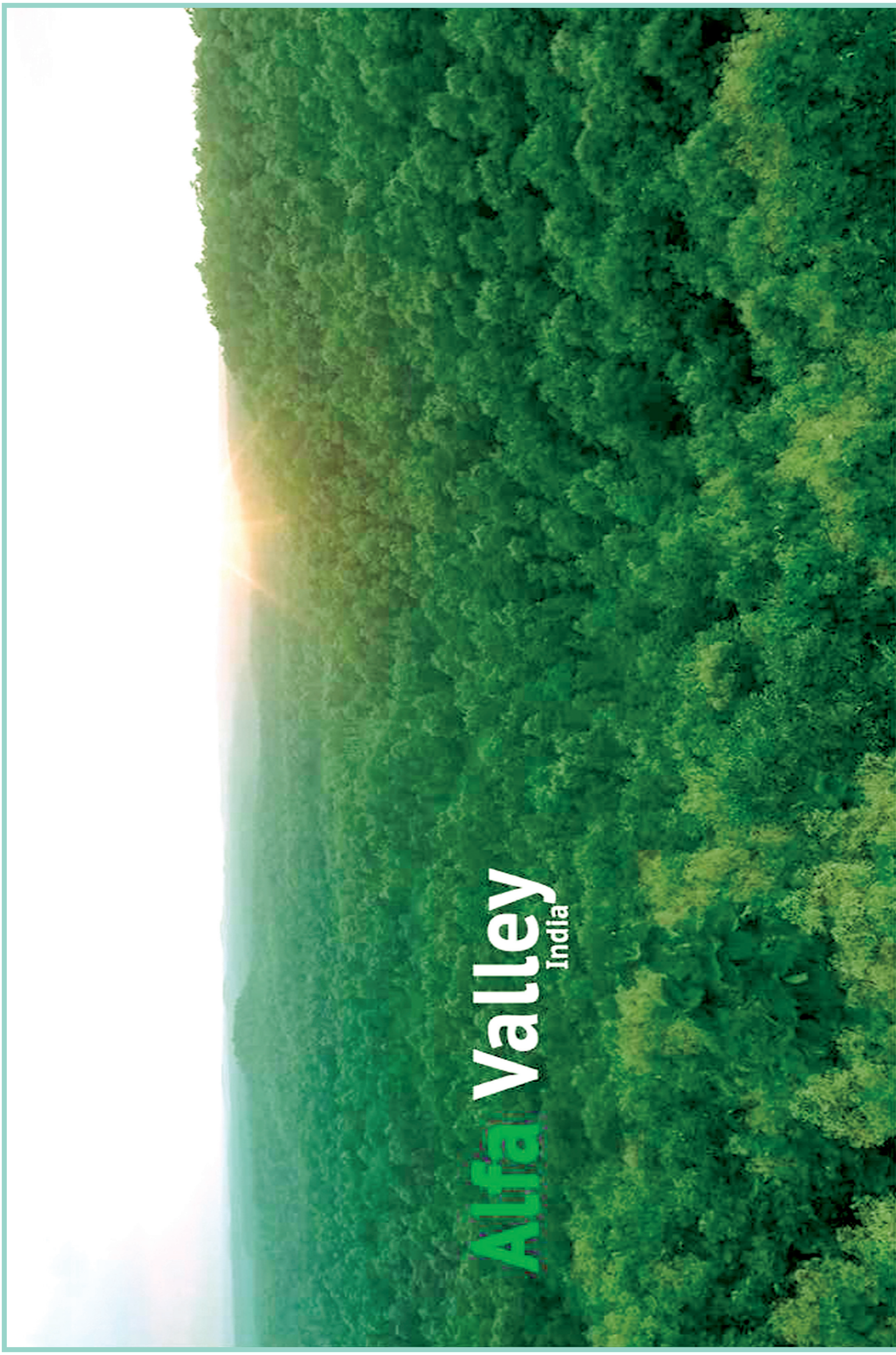
Alfa Valley
India

नॉवेल, म्यूजिक और पॉडकास्ट से मिला सुकूनः रसिका दुग्गल

बॉलीवुड अभिनेत्री रसिका दुग्गल ने हाल ही में अपने प्रेरणादायक अनुभवों को प्रशंसकों के साथ साझा किया। इंस्टाग्राम पर अपनी एक मनमोहक तस्वीर साझा करते हुए, जिसमें वह अपने बालों के साथ खेलती नजर आ रही हैं, रसिका दुग्गल ने एक विस्तृत कैप्शन लिखा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह हमेशा ऐसी चीजों की तलाश में रहती हैं जो उनके मन के भावों को सकारात्मक रूप से बदल सकें और उन्हें आंतरिक शक्ति प्रदान करें। रसिका ने अपने पोस्ट में लिखा, इंस्पिरेशन की तलाश मेंज हमेशा कुछ ऐसा ढूंढती रहती हूं जो मेरे एहसासों को थोड़ा बदल दे, मेरे मन की बात कह देंज पिछले कुछ महीनों में कुछ चीजें मेरे लिए खास प्रेरणा का स्रोत रही हैं। इस दौरान, रसिका ने विशेष रूप से विश्व प्रसिद्ध फिगर स्केटर एलिसा लियू का उल्लेख किया, जिनकी शानदार वापसी ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उन्होंने लिखा, एलिसा की वापसी प्रेरणादायक रही। यह एक ऐसी वापसी की कहानी है, जिसमें अपार मेहनत, अटूट आत्मविश्वास और अपने स्वयं के रास्ते पर चलने की ताकत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनकी उपलब्धियां अविश्वसनीय रूप से शानदार रही हैं, जिसमें ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे प्रतिष्ठित बड़े मंचों पर उनकी विजय भी शामिल है। साहित्य से भी रसिका को गहरी प्रेरणा मिली।

बेटी दुआ की तस्वीर साझा कर दी जानकारी, दीपिका पादुकोण दूसरी बार बनने वाली हैं मां

बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर साझा की है, जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और प्रशंसकों के बीच हलचल पैदा कर दी है। दीपिका और रणवीर सिंह ने एक कोलैबोरेशन पोस्ट के जरिए अपनी बेटी दुआ पादुकोण की एक बेहद प्यारी फोटो शेयर की है। इस तस्वीर की खास बात यह है कि नन्ही दुआ के हाथ में एक प्रेग्नेंसी टेस्ट किट नजर आ रही है, जिस पर दो स्पष्ट गुलाबी लाइनें दिख रही हैं। इसे दीपिका और रणवीर की तरफ से अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का आधिकारिक ऐलान माना जा रहा है। दीपिका ने पोस्ट के कैप्शन में किसी शब्द का इस्तेमाल न करते हुए केवल ईवल आई (बुरी नजर से बचाने वाला) इमोजी बनाया है। जैसे ही यह पोस्ट सामने आई, कमेंट सेक्शन बधाइयों से भर गया। बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने इस कपल को शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया है। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने बधाई लिखकर अपनी खुशी जाहिर की, वहीं कियारा आडवाणी ने ढेर सारे हार्ट और ईविल आई इमोजी के साथ कपल को विश किया। कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर सहित अन्य कई फिल्मी सितारों के कमेंट्स ने इस खबर पर लगभग मुहर लगा दी है कि दीपिका और रणवीर के जीवन में एक और नन्हा मेहमान आने वाला है। खबर लिखे जाने तक इस पोस्ट को लाखों लोग लाइक कर चुके हैं। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण नवंबर 2018 में शादी के बंधन में बंधे थे। उनकी पहली बेटी, दुआ पादुकोण का जन्म सितंबर 2024 में हुआ था।

गिन्नी वेड्स सनी 2 को लेकर मेधा की यामी से हो रही तुलना

बॉलीवुड गलियारों में अपकमिंग फिल्म गिन्नी वेड्स सनी 2 को लेकर खूब चर्चा हो रही हैं। इस बार मेधा शंकर को इसकी मुख्य भूमिका में देखा जाएगा। यह फिल्म 2020 में आई सफल रोमांटिक कॉमेडी गिन्नी वेड्स सनी का सीक्वल है। इसी कारण उनकी तुलना स्वाभाविक रूप से पहली फिल्म की नायिका यामी गौतम से की जा रही है, जो अपने प्रदर्शन के लिए दर्शकों द्वारा खूब सराही गई थीं। हालांकि, मेधा शंकर ने इन तुलनाओं पर अपनी बेबाक राय रखते हुए स्पष्ट किया है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक विशेष बातचीत में मेधा शंकर ने इन तुलनाओं को सिरे से खारिज करते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यामी गौतम और आदित्य धर दोनों को बहुत पसंद करती हूं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि मैं उनकी कितनी बड़ी प्रशंसक हूं। उन्होंने यामी गौतम की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा, यामी हमेशा से ही एक बेहतरीन अभिनेत्री रही हैं, और कभी-कभी बेहतरीन प्रतिभा को पहचान मिलने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन मुझे यकीन है कि उनका समय ज़रूर आएगा।

सैमसन का शतक, सीएसके ने दर्ज की आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी जीत

नई दिल्ली ■ एजेंसी

चेन्नई सुपरकिंग्स ने आईपीएल में इतिहास रच दिया. सीएसके ने मुंबई इंडियंस को आईपीएल के 33वें मैच में 103 रन से हराकर सीजन की तीसरी जीत दर्ज की. सीएसके की यह आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी जीत है वहीं मुंबई की आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी हार है. मुंबई की सात मैचों में यह पांचवीं हार है. सीएसके की जीत में संज सैमसन के नाबाद शतक का अहम रोल रहा जबकि गेंदबाजी में स्पिनर अकील हुसैन और नूर अहमद ने अपनी फिरकी में मुंबई के छह बल्लेबाजों को फंसाया. सीएसके की ओर से रखे गए 208 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम 19 ओवर में 104 रन पर ढेर हो गई. मुंबई के लिए तिलक वर्मा ने 37 वहीं सूर्यकुमारा यादव ने 36 रन बनाए.

मुंबई इंडियंस की पारी की शुरूआत बेहद खराब रही. क्विंटन डी कॉक (7), दानिश मालेवार (0), और नमन धीर (0) सस्ते में पवेलियन लौट गए. मिडिल ऑर्डर में सूर्यकुमार यादव (36) और तिलक वर्मा (37) ने संघर्ष दिखाते हुए पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अकील हुसैन की घातक गेंदबाजी के सामने वे भी टिक नहीं पाए. हुसैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अकेले 4 विकेट चटकाए. कप्तान हार्दिक पांड्या (12) और शेरफेन रदरफोर्ड (0) भी नूर अहमद का शिकार बने. जिससे टीम संकट में आ गई. मुंबई ने 100 रन पर अपने 8 विकेट गंवा दिए थे. ओवर्टन ने मुंबई को आठवां वहीं अंशुल कम्बोज ने शार्दुल ठाकुर को आउट कर नौवां झटका दिया. शार्दुल छह रन बनाकर आउट हुए.

संजू ने शतक जड़कर बना डाले पांच बड़े रिकॉर्ड

तीसरे ओवर में गायकवाड़ ने ए एम गजनफर (25 रन देकर दो विकेट) के खिलाफ शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन तिलक वर्मा ने उनका एक शानदार कैच लपक लिया. सीएसके टीम में मौजूद मुंबई के खिलाड़ियों सरफराज खान (14) और शिवम दुबे (05) के लिए यह घर वापसी बिल्कुल भी सुखद नहीं रही. सरफराज के ऑन-साइड में दो चौके लगाने के बावजूद मिचेल सैंटनर ने अगली गेंद विकेटों की लाइन में ही फेंकी. सरफराज ने अपना ट्रेडमार्क स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे उनके विकेटों से जा टकराई. नौवें ओवर में गजनफर की गेंद चौथे नंबर पर उतरे भारत के ऑलराउंडर दुबे के बल्ले के अंदरूनी किनारे से टकराकर सीधे विकेटों में जा लगी.

वैभव का आईपीएल में तहलका, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज

नई दिल्ली ■ एजेंसी

आईपीएल 2026 के 32वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रन से हरा दिया. इस मैच में पहले राजस्थान ने बल्लेबाजी की थी और 159 रन बनाए थे जिसके बाद लखनऊ की टीम केवल 119 रन ही बना सकी. इस मैच में भले ही वैभव सूर्यवंशी केवल 8 रन बनाकर आउट हुए लेकिन उन्होंने आईपीएल करियर में 500 रन पूरा कर लिए. एक ओर जहां वैभव गेंद खेलने के हिसाब से सबसे तेज 500 आईपीएल रन बनाने वाले बल्लेबाज बने तो वहीं, आईपीएल इतिहास में सबसे कम्र उम्र में 500 रन पूरा करने का कमाल कर दिखाया.

ऐसा पहले बल्लेबाज बने

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 500 रन बनाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. उनसे पहले किसी भी बल्लेबाज ने 200 का स्ट्राइक रेट रखते हुए 500 आईपीएल रन पूरे नहीं किए हैं जो अपने-आप में एक ऐतिहासिक बात है.

सबसे कम्र उम्र में 500 आईपीएल रन

15 साल 26 दिन - वैभव सूर्यवंशी
19 साल164 दिन - पृथ्वी शॉ
19 साल195 दिन - संजू सैमसन
19 साल 220 दिन - ऋषभ पंत

करियर में पहली बार हुआ ऐसा

ऐसा पहली बार हुआ है जब अपने आईपीएल करियर में वैभव सूर्यवंशी ने किसी बॉलर के खिलाफ मेडन ओवर खेला है. इससे पहले कभी भी वैभव ने आईपीएल में मेडन ओवर नहीं खेला था. बता दें कि मोहसिन खान के ओवर में वैभव आउट हुए और उनके खिलाफ एक भी रन भी नहीं बना पाए.

आईपीएल 2026 में वैभव का धमाका

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं. उन्होंने 7 मैचों में 220.86 के स्ट्राइक रेट से 254 रन बनाए हैं. वह इस सीजन में रॉयल्स के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और कुल मिलाकर चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, उनके बेहतरीन प्रदर्शन ने जल्द ही भारत के लिए डेब्यू करने की उम्मीदें भी जगा दी हैं.

खेल में राजनीति कर रहा पाकिस्तानः भारत में होने वाले टूर्नामेंट से नाम वापस लिया

कराची ■ एजेंसी

दक्षिण एशिया के बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ विमेंस चैंपियनशिप 2026 से पाकिस्तान ने अपना नाम वापस ले लिया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों के चलते यह फैसला लिया गया है। यह टूर्नामेंट 25 मई से छह जून तक गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जाना है।

पाकिस्तान के हटने के बाद अब इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव शामिल हैं। ढाका में हुए ड्रॉ में इन टीमों को दो समूहों में बांटा गया है, जिससे प्रतियोगिता का रोमांच बरकरार रहेगा। यह फैसला

पाकिस्तान महिला फुटबॉल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हाल के वर्षों में टीम धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वापसी कर रही थी और इस टूर्नामेंट को खुद को साबित करने का बड़ा मौका माना जा रहा था। लेकिन एक बार फिर राजनीतिक तनाव ने खेल पर असर डाला और खिलाड़ियों का यह मंच छिन गया। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत में होने वाले किसी खेल आयोजन से दूरी बनाई हो। इससे पहले भी पाकिस्तान ने पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप और एशिया कप में अपनी टीम नहीं भेजी थी।

ओलिंपिक 2028 में क्रिकेट मुकाबले पोमोना में खेले जाएंगे, स्टेडियम का काम शुरू

नई दिल्ली ■ एजेंसी

साल 2028 में होने वाले लॉस एंजिल्स ओलिंपिक के लिए क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। कैलिफोर्निया के पोमोना में बुधवार को हुए भूमि पूजन के साथ ही क्रिकेट की 128 साल बाद ओलिंपिक में वापसी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है।

सभी मुकाबले लॉस एंजिल्स से लगभग 50 किलोमीटर दूर पोमोना स्थित फेयरग्राउंड्स मैदान पर खेले जाएंगे। ओलिंपिक में क्रिकेट मैच 12 जुलाई से 29 जुलाई 2028 तक आयोजित होंगे। साल 1900 में पेरिस ओलिंपिक में क्रिकेट को

शामिल किया गया था। इसके बाद क्रिकेट को ओलंपिक्स में नहीं लिया गया। पेरिस ओलंपिक्स के क्रिकेट इवेंट में सिर्फ दो टीमों इंग्लैंड और फ्रांस ने हिस्सा लिया था। इसमें इंग्लैंड ने गोल्ड और फ्रांस ने सिल्वर जीता था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह ने इस अवसर को खेल के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट वैश्विक खेल बनने की दिशा में बड़ी छलांग लगा रहा है। ओलिंपिक का हिस्सा बनना गर्व की बात है और हमें विश्वास है कि यह वेन्यू खेलों के दौरान केंद्र बिंदु बनेगा और अमेरिका में क्रिकेट की एक स्थायी विरासत छोड़कर जाएगा।

6 टीमें और टी-20 फॉर्मेट में होंगे मुकाबले

लॉस एंजिल्स ओलिंपिक में क्रिकेट एक आधुनिक फॉर्मेट में लौटेगा। इसमें मेंस और विमेंस दोनों कैटेगरी के लिए अलग-अलग टी-20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। हर टीम को 15 सदस्यीय स्क्वॉड की अनुमति होगी। विजेता टीमों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाएंगे।

लगातार तीसरा मैच हारी भारतीय टीम

जोहानिसबर्ग। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही पांच टी20 मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। बुधवार को खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने कप्तान एल वोल्वार्ड्ट के शतक की बदौलत मैच 9 विकेट से जीता। भारतीय टीम की यह लगातार तीसरी हार थी। दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। भारतीय टीम ने चार विकेट पर 192 रन बनाए थे। टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने आईं शैफाली वर्मा ने 64 रनों की पारी खेली।

अब आप भी बन सकते हैं
ग्लोबल रिपोर्टर
अपने आस-पास होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियां, घटना-दुर्घटना की खबर, फोटो या वीडियो हमें वाट्सएप करें
7999509078
ना केबल कनेक्शन की झंझट, ना ही सेट-टॉप बॉक्स का खर्चा
ग्लोबल हेराल्ड न्यूज़ अब IPTV* पर भी
बस एक बार गूगल करें और देखें हमेशा ताज़ातरीन खबरें
www.globalheraldtv.com
ग्लोबल हेराल्ड NATIONAL HERALD
न्यूज पेपर न्यूज चैनल वेब टीवी
globalheraldeditor@gmail.com

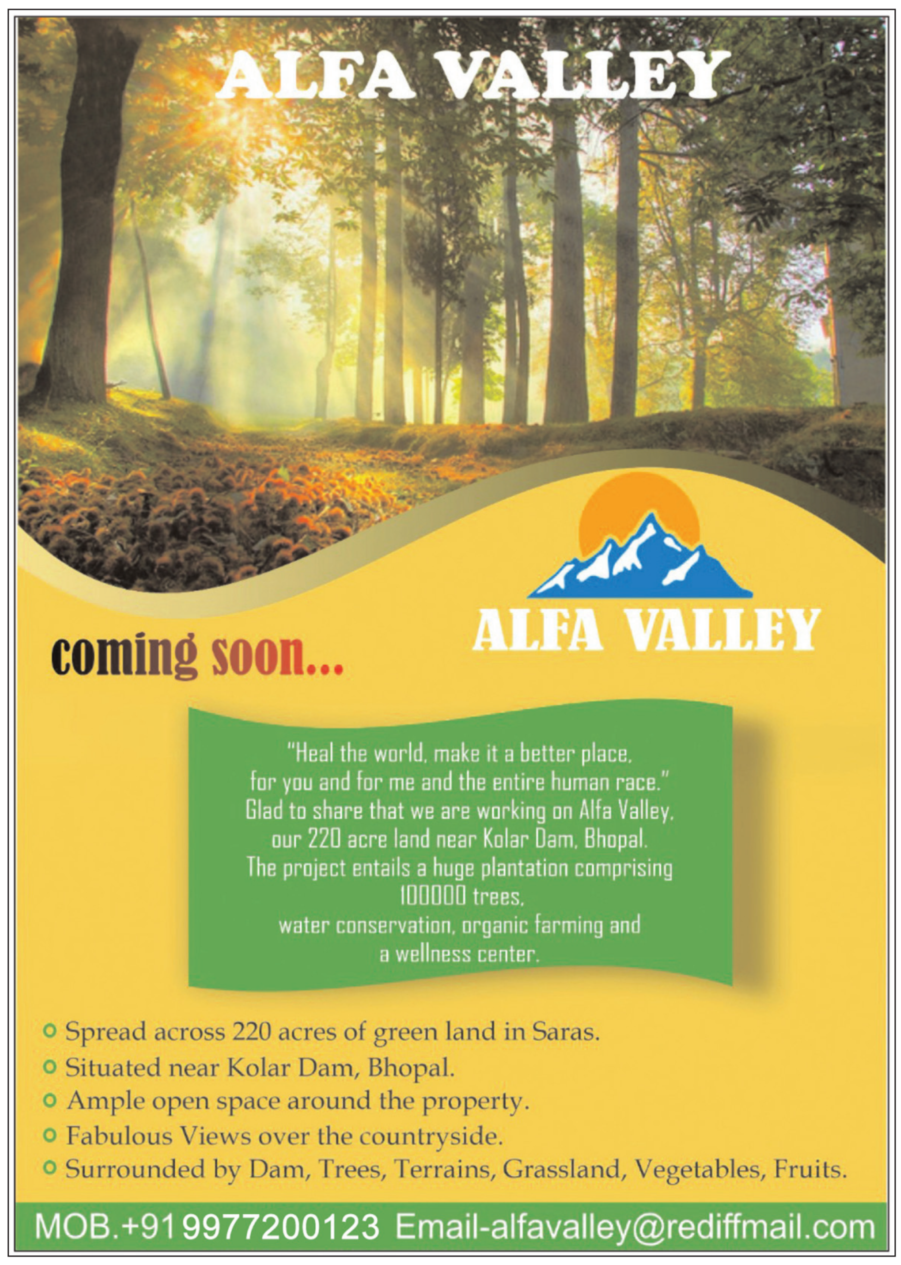

प्रकाशक एवं मुद्रक **विष्णु गोयल** द्वारा स्वामी शिवा पब्लिकेशन के लिए 1-ए, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स एबी रोड, इंदौर, मध्यप्रदेश से प्रकाशित एवं पी.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रा.लि. रिलायंस पेट्रोल पम्प के पीछे, सेंटर पाइंट, मांगलिया बायपास, इंदौर, मध्यप्रदेश से मुद्रित। Epaper_www.globalherald.news
प्रधान संपादक -**विष्णु गोयल,** सलाहकार संपादक- **डॉ.शिशिर उपाध्याय,** प्रदेश संपादक- **दिलीप शर्मा,** स्थानीय संपादक **सत्येन्द्र जैन***(*समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार)। मोबाइल नं.:-7999509078, आर.एन.आई. नं. MPHIN/2012/41876, email- editor@nationalherald.org/globalheraldeditor@gmail.com